Registration No. RAJBIL /2016 / 69093
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

लघु उद्योग भारती

UDYOG TIMES

Volume -8 Issue-11 September- 2025
Total Pages - 56 Price - Rs. 10

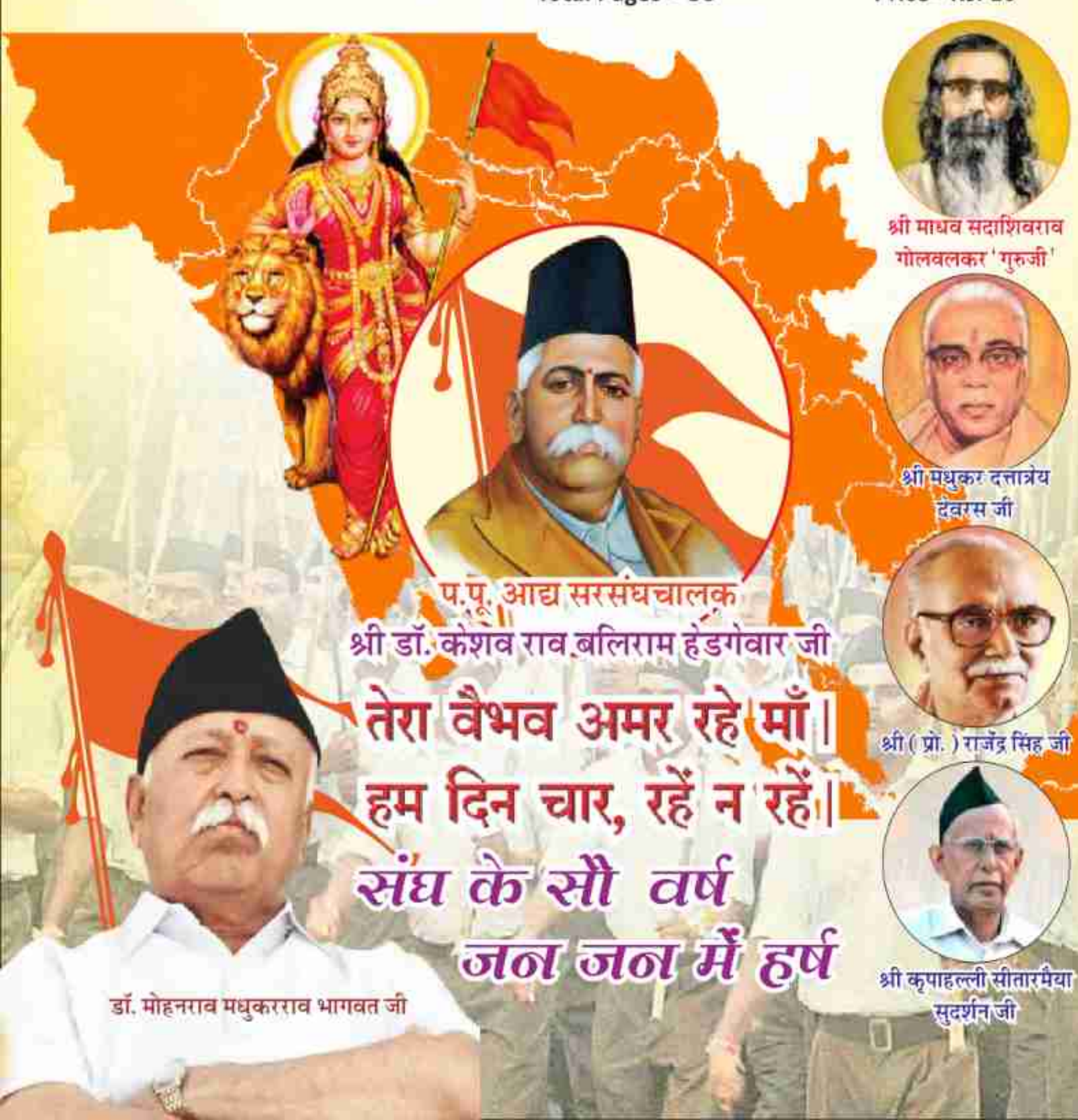

श्री माधव सदाशिवराव गोलवलकर 'गुरुजी'

श्री मधुकर दत्तात्रेय देवरस जी

श्री (प्रो.) राजेंद्र सिंह जी

श्री कृपाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन जी

प.पू. आद्य सरसंघचालक
श्री डॉ. केशव राव बलिराम हेडगेवार जी

तेरा वैभव अमर रहे माँ।
हम दिन चार, रहें न रहें।

संघ के सौ वर्ष
जन जन में हर्ष

डॉ. मोहनराव मधुकरराव भागवत जी

Government of Rajasthan

Shri Narendra Modi
Hon'ble Prime Minister
India

Shri Bhajanlal Sharma
Hon'ble Chief Minister
Rajasthan

Shri Rajyavardhan Rathore
Hon'ble Minister for
Industry and Commerce
Rajasthan

Shri K.K. Vishnoi
Hon'ble Minister of State for
Industry and Commerce
Rajasthan

INDIA'S BIGGEST STONE INDUSTRY SHOWCASE

13th

INDIA STONEMART2026

Stone for Sustainability

5 - 8 February, 2026

JAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

REGISTER NOW

stonemart-india.in

Organiser

CDOS
Centre for Development of Stones

Principal Sponsor

RIICO

Co-Organiser

LAGHU UDYOG BHARATI

Fair Sponsor

RK MARBLE

info@stonemart-india.in | www.stonemart-india.in | +91-7300053633

UDYOG TIMES

OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

Volume -8 Issue - 11 September 2025

Editorial Board

■ *Patron*

Shri Ghanshyam Ojha, National President	098290-22896
Shri Prakash Chandra ji, National Org. Secretary	099299-93660
Shri Om Prakash Gupta, National Gen. Secretary	095602-55055

■ *Editor*

Dr. Kirti Kumar Jain	094141-90383

■ *Co-Editor*

Dr. Sanjay Mishra	098295-58069

विवरणिका

Editorial	03
संघ राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार	05
संघ के सौ वर्ष	06
विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था	10
प्राचीन भारत की आर्थिक व्यवस्था	12
औद्योगिक नगरी भिवाड़ी	16
प्रवासी राजस्थानी	23
Indo - Japan New Tech	25
उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश	28
समालखा उद्यमी सम्मेलन	32
LUB's NEWS in Brief	43

Price - 10/- *Life Membership 1000/-*

Corporate & Head Office :
Shri Vishwakarma Bhawan 48, Deen Dayal Upadhyay Marg, Rouse Avenue, New Delhi-110002
Website : www.lubindia.com
Email : headoffice@lubindia.com
Ph.: 011-23238582
Registered Office :
Plot No. 184, Shivaji Nagar, Nagpur-440011
Ph.: 0712-2533552

GST Announcements - Not just Reforms, a Lifeline for MSMEs

Editorial

Dr. Kirti Kumar Jain
kkjain383@gmail.com

It was expecting something of this sort to be announced after Trump's recent tariff bomb. But new GST slabs exceeded all expectations.

First reaction perhaps will be that the most transformative change is not just about the new tax rates, it is more about the systemic simplification that accompanies them. The GST Council's decision to streamline the tax slabs from 4 to 2 (5 percent and 18 percent) directly addresses a long-standing complaint from all businesses, small or big - the confusion and compliance burden caused by a multiplicity of these rates. For a small business, this change means less time will now be spent on complicated tax filings and more time focused on what truly matters, which is, creating products, serving customers, and growing their business.

MSMEs will now benefit from the correction of the inverted duty structure. In the past whenever I spoke to MSME owners across cities, they would complain that their working capital was locked up in unutilized Input Tax Credit because the tax on their raw materials was higher than the tax on their final product. However, the new, rationalized rates on items like man-made textiles, handicrafts, and agricultural machinery will finally correct this anomaly, which is a huge relief to small businesses working on limited capital. This will unlock vital capital, giving these businesses the much-needed liquidity to invest in new technology, hire more people, or even to expand their operations.

The reforms on registration and refunds are also nothing short of a game-changer. These will be government's true support for small businesses. MSMEs in times of distress. The new simplified registration process, promising approvals for low-risk applicants in just three days, will significantly reduce the time and effort required for new ventures to formalize. Even exporters will benefit from this because the automated refund mechanism will directly enhance the ease of doing business for a sector that contributes tremendously to the GDP of our nation.

Isn't it a virtuous cycle! The logic is very simple; lower taxes lead to cheaper products, which in turn boosts demand, and that demand is met by a more agile and competitive MSME sector. For the millions of entrepreneurs who power our economy, this is more than just a tax cut; it is a vote of confidence.

□□□

निश्चय राजस्थान

श्री भजन लाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

मनदर्पण

MENTAL WELLBEING OF ADOLESCENTS

बेहद जरूरी है !

- स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य को पहचानना
- अपने दोस्तों/क्लासमेट/रूम मेट के मानसिक स्वास्थ्य को पहचानना

मानसिक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं

- तनाव का सामना करना
- अपनी क्षमताओं का उपयोग करना
- सदैव सीखने की लगन रखना
- अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करना
- समुदाय में योगदान करना
- सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना

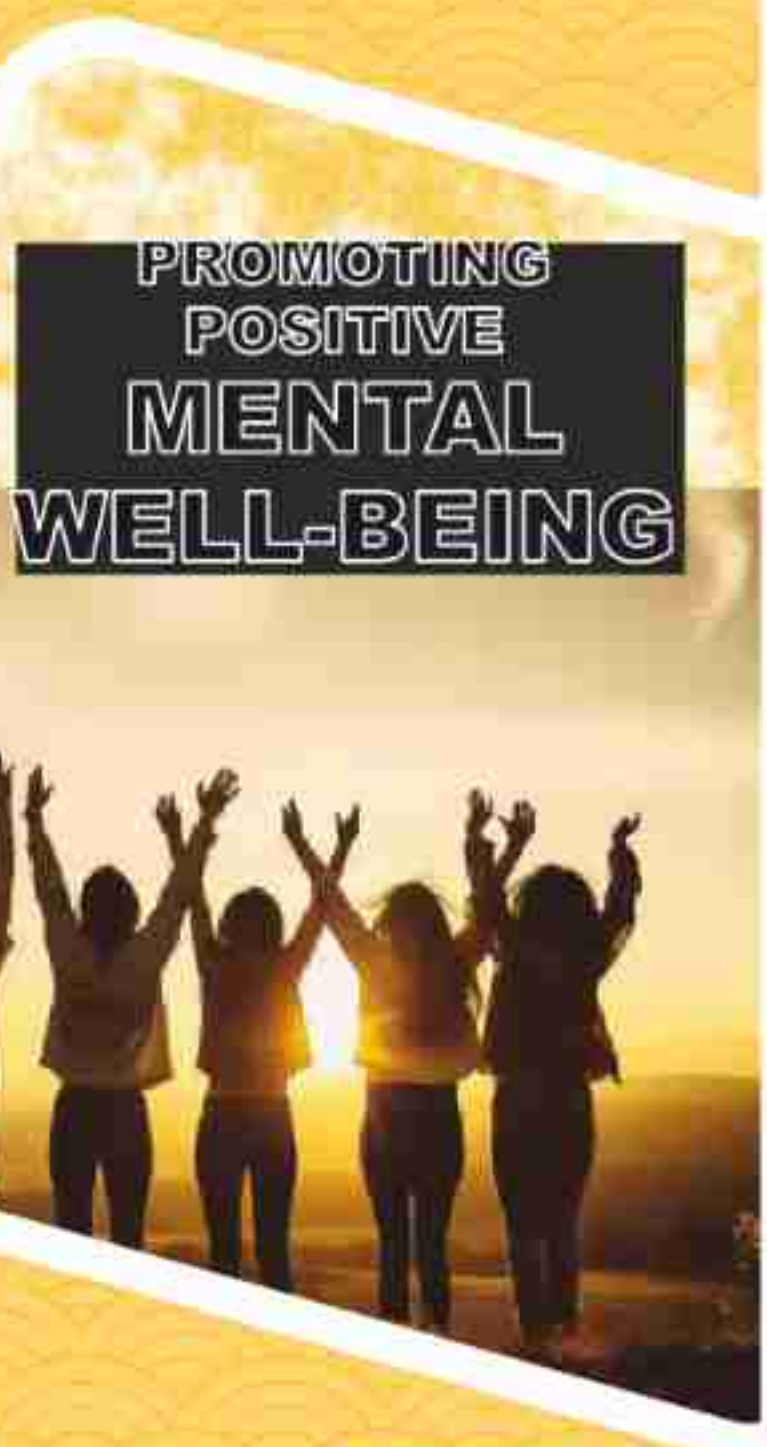

मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अन्य परामर्श के लिए नि:शुल्क हेल्पलाइन पर संपर्क करें-

राष्ट्रीय टेली मानस
नि:शुल्क हेल्पलाइन
14416, 18008914416

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं
(आईईसी) राजस्थान, जयपुर

'संघ राष्ट्र-चेतना का पुण्य अवतार है'

संघ की राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका को प्रतिष्ठित करते हुए पहली बार डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

(दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करते हुए उनके विशेष सम्बोधन का संपादित अंश)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में भाग लिया और संघ की देश सेवा व राष्ट्र निर्माण में निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि **"संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता नहीं दिखाई। चाहे प्रतिबंध लगे हों या साजिशें हुई हों, संघ का मंत्र हमेशा यही रहा - जो अच्छा है, जो कम अच्छा है, सब हमारा है।"**

संघ शताब्दी वर्ष पर डाक टिकट और सिक्का जारी करते हुए प्रधानमंत्री और साथ में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मान्य सह सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबोले

पीएम मोदी ने इस अवसर पर संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक जो लगातार देश सेवा में जुटे हैं। समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक इस डाक टिकट में है। इन प्रतीकों के जरिए RSS के योगदान और समाज सेवा की झलक देशवासियों तक पहुंचेगी। मैं इसके लिए देश को बधाई देता हूं।

इस खास सिक्के के आगे अशोक स्तंभ का चिह्न बना है। वहीं, सिक्के के पिछले हिस्से में भारत माता और RSS कार्यकर्ताओं की छवि देखी जा सकती है। जारी किए गए डाक टिकट पर 1963 की RSS कार्यकर्ताओं की परेड की तस्वीर है। यह सिक्का शुद्ध चांदी का है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है– 'राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं न मम।'

100 साल पहले RSS की स्थापना संयोग नहीं-

100 साल पहले RSS की स्थापना मात्र एक संयोग नहीं थी, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और राष्ट्र चेतना का "कालजयी पुनरुत्थान" था। अन्याय पर न्याय और अंधकार पर प्रकाश की जीत – यही भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। RSS उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है, जो समय–समय पर नई चुनौतियों से निपटने के लिए प्रकट होती रही है।

संघ का मूल मंत्र है 'राष्ट्र प्रथम'-

RSS और उसके स्वयंसेवकों का उद्देश्य हमेशा एक रहा है – राष्ट्र प्रथम। संघ ने जिस पद्धति को चुना, वह थी व्यक्ति निर्माण के जरिए राष्ट्र निर्माण। शाखा संघ की उस विराट धारा का माध्यम बनी जिसने समाज को संगठित और सशक्त बनाया।

घुसपैठ और जनसंख्या बदलाव बड़ी चुनौती-

वर्तमान में देश के सामने कई चुनौतियां हैं और इन्हीं में से बड़ी चुनौती है घुसपैठ। इसके अलावा, दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता और जनसंख्या के डेमोग्राफिक बदलाव के षड्यंत्र जैसी चुनौतियों से हमारी सरकार तेजी से निपट रही है। लेकिन संतोष की बात है कि RSS ने भी इन मुद्दों से निपटने के लिए ठोस रोडमैप तैयार किया है।

□□□

राष्ट्र निर्माण की सतत साधना में संलग्न संघ के सौ वर्ष

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। स्थापना के बाद से लगातार संघ का विस्तार, इसकी शक्ति तथा बढ़ते प्रभाव को देखकर लोगों में संघ कार्य को जानने तथा उसे समझने की उत्सुकता बढ़ रही है।

संघ यात्रा

मनमोहन वैद्य

प्रख्यात चिंतक एवं मान्य सह सरकार्यवाह
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

संघ को समझना है, तो उसके संस्थापक आद्य सर संघचालक डॉ. हेडगेवार को समझना आवश्यक है। डॉ. हेडगेवार जन्मजात देशभक्त थे तथा अंग्रेजों की गुलामी को लेकर उनके मन में तीव्र चिढ़ थी, आक्रोश था, जो उनके बाल्यावस्था में अनेक रूपों में प्रकट होता दिखता है। परंतु उनके मन में यह विचार भी था कि केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करना बीमारी के लक्षण का इलाज करने के समान है। इसलिए पहले इस पर विचार करना होगा कि इतने विशाल, समृद्ध और संपन्न भारतीय समाज को गुलाम बनने की नौबत किस कारण से आई? इसलिए मूल बीमारियों का इलाज करने हेतु समाज में आत्म–जागृति, स्वाभिमान, एकता, परस्पर भाईचारा, अनुशासन और राष्ट्रीय चारित्र्य निर्माण के मूलभूत उद्देश्य से स्वतंत्रता प्राप्ति के सभी प्रयासों में सक्रिय रहते हुए भी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना अक्तूबर 1925 को विजयदशमी के दिन की।

संपूर्ण भारत की पहचान जिससे है, उस अध्यात्म आधारित एकात्म और सर्वांगीण जीवन–दृष्टि जिसे दुनिया हिंदुत्व अथवा हिंदू जीवन दृष्टि के नाते जानती है, उस हिंदुत्व को जगाकर संपूर्ण समाज को एक सूत्र में जोडकर निर्दोष और गुणवान हिंदू समाज के संगठन का यह कार्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू हुआ। उस समय के सभी विचारक, मूर्धन्य चिंतक तथा नेतृत्व से परिचय तथा निकट संपर्क होते हुए भी डॉ. हेडगेवार की दृष्टि विशिष्ट (unique), व्यापक तथा सर्व समावेशी और दूरगामी थी। His vision was well grounded and much ahead of other contemporary leaders. उस कालखंड में भारत में अनेक आध्यात्मिक,

सामाजिक या अन्य संगठन शुरू हुए और भारत को संवारने में उनका श्रेष्ठ योगदान रहा है। उसी तरह, हिंदू समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का एक और संगठन शुरू होना अस्वाभाविक नहीं था। परंतु पहले दिन से यह स्पष्ट था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के अन्तर्गत एक संगठन या संस्था बनकर नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन बनकर काम करेगा। एक ज्येष्ठ चिंतक ने कहा है कि परिकल्पना की दृष्टि से संघ और हिंदू समाज समव्याप्त (co-terminus) है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संघ और हिंदू समाज एकात्म है। इसलिए डॉ. हेडगेवार ने 'वादोनोवलम्ब्या:' (वाद–विवाद में न पड़ते हुए) और 'सर्वेषाम् अविरोधेन' (किसी से विरोध न रखते हुए) संपूर्ण समाज को संगठित करने का संकल्प लिया। वर्तमान सरसंघचालक डॉ. मोहन जी भागवत ने एक वक्तव्य में कहा था, "उन्होंने हमारा विरोध

करने का भले ही तय किया हो, हमारा विरोधी कोई नहीं है। उनके संघ विरोध से संघ को नुकसान न हो, यह सावधानी रखते हुए हम उन्हें आत्मीयतापूर्वक मिलने जाएंगे।"

व्यक्ति–निर्माण तथा समाज संगठन का यह सदा सर्वदा परिस्थिति निरपेक्ष 'नित्य' कार्य अविरत चलता रहेगा तथा समय–समय पर परिस्थितिवश समाज में उठने वाले अन्य आह्वान से निपटने के लिए 'अनित्य' कार्य में भी स्वयंसेवक अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे, यह वस्तुपाठ भी हेडगेवार जी ने अपने आचरण से सिखाया।

संघ स्थापना से पहले 1921 में महात्मा गांधी के आवाहन पर हुए असहयोग आंदोलन (non-cooperation) में डॉ. हेडगेवार सहभागी हुए थे। उन्हें एक वर्ष कारावास भी सहना पड़ा था। संघ स्थापना के पश्चात् महात्मा गांधी के आह्वान पर सविनय अवज्ञा (civil-disobedience) आंदोलन के तहत 1930 के सत्याग्रह में ('अनित्य' कार्य) स्वयंसेवक के नाते हेडगेवारजी अन्य स्वयंसेवकों के साथ सहभागी हुए थे

और 9 महीने कारावास में रहे। परंतु उसी के साथ संघ का 'नित्य' कार्य अविरत चलता रहे, इसके लिए उन्होंने सरसंघचालक का दायित्व अपने सहयोगी डॉ.लक्ष्मण वासुदेव परांजपे को सौंपा था। यह 'नित्यानित्य विवेक' हेडगेवार जी की विशेषता थी, जो न केवल महत्वपूर्ण थी, बल्कि संघ कार्य की आगे की यात्रा के लिए मार्गदर्शक भी थी।

समाज से धन लेकर समाजहित के कार्य करने की परंपरा भारत में पहले भी थी, आज भी है। परंतु संघ कार्य देश कार्य है, मेरा कार्य है और यह समाज से धन लेकर नहीं, स्वयंसेवकों से गुरु–दक्षिणा के रूप में प्राप्त समर्पण राशि से ही चलेगा, ऐसा अनोखा विचार हेडगेवार जी ने किया और उसे लागू किया, जो आज भी चल रहा है। इसी तरह श्रेष्ठ आदर्श व्यक्ति को गुरु मानने की परंपरा भारत में सदियों से रही है और आज भी प्रचलित है। परंतु संपूर्ण समाज का संगठन होने के बावजूद संघ में कोई व्यक्ति गुरु नहीं है। हिंदू समाज जितना प्राचीन है, उसका गुरु, हिंदुत्व का प्रतिनिधि और उतना ही प्राचीन कोई प्रतीक हो सकता है, यह सोच कर भगवा ध्वज गुरु के नाते संघ में स्थापित हुआ।

स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता (आयरिश मूल की मार्गरिट नोबेल) ने 1906 में स्वतंत्र भारत के ध्वज का पहला नमूना बनाया था। उसमें भगवा कपड़े पर पीले रंग में वज्र अंकित था।

स्वतंत्र भारत का राष्ट्रध्वज कैसा हो, इस पर विचार के लिए 1931 में कांग्रेस कार्यसमिति ने ध्वज समिति (Flag Committee) बनाई थी। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मास्टर तारा सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभि सीतारमैया (संयोजक), काका कालेलकर और डॉ. हार्डिकर इसके सदस्य थे। सभी ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव रखा कि भारत का ध्वज एक रंग का और वह भी भगवा हो। कारण, यह रंग भारत के सभी लोगों को सहज

स्वीकार्य है और यह प्राचीन भारत के इतिहास के साथ दीर्घ काल से जुड़ा हुआ है। समिति का प्रस्ताव था कि आयताकार भगवा कपड़े वाले ध्वज पर नीले रंग का चरखा अंकित हो। आर्य समाज और हिंदू महासभा के ध्वज भी भगवा ही थे, जिस पर सूर्य या ओंकार अंकित है। उस समय के प्रस्तावित या प्रचलित सभी ध्वज पर कोई न कोई चिह्न अंकित दिखता है। परंतु 1927 से संघ में प्रचलित गुरु के स्थान पर स्थापित भगवा ध्वज पर कोई चिह्न अंकित नहीं है। कारण, संघ, समाज के अन्तर्गत एक संस्था या संगठन न होकर संपूर्ण समाज का संगठन है, यह मूल संकल्पना है।

राष्ट्रीय चारित्र्य निर्माण और सामूहिक गुणों की उपासना (साधना) हेतु तथा अपने ध्येय का नित्य स्मरण करने हेतु दैनन्दिन एकत्र होने के लिए शाखा नामक कार्यपद्धति संघ में विकसित हुई। दैनंदिन सामान्यतः एक घंटा चलने वाली शाखा में यह भाव जगाया जाता है कि भारत का संपूर्ण समाज एक है, समान है और सभी अपने हैं। साथ ही, उद्यम, साहस, धैर्य, शक्ति, बुद्धि और पराक्रम जैसे गुण विकसित करने के लिए खेल आदि विविध कार्यक्रम शाखा पर होने लगे। अनुशासन, एकता, वीरत्व और सामूहिकता का भाव निर्माण करने हेतु परेड, बैंड के ताल पर पथ–संचलन (Root March) और योग–व्यायाम (पीटी) जैसे कार्यक्रम, जो ब्रिटिश सेना से स्वीकार किए गए, शाखा में होने लगे और आज भी हो रहे हैं।

शाखा वास्तव में सामूहिक गुणों की उपासना और व्यक्तिगत गुणों का सामूहिक अभ्यास का एक कार्यक्रम है, साधन है। समाज को अपना मान कर उसके लिए कुछ न कुछ (कभी–कभी सब कुछ) देने का (वापस लौटाने का) संस्कार इसी शाखा से प्राप्त होता है। इस विचार को व्रत के नाते स्वीकार कर जीवन भर उसका पालन करने का संकल्प लेकर जीने वाले सहयोगी कार्यकर्ताओं को देखकर, उनके संपर्क से प्रेरित होकर आनंद के साथ हजारों–लाखों कार्यकर्ताओं के द्वारा यह समर्पण यज्ञ अविरल चल रहा है।

आज संपूर्ण भारत के कुल 924 जिलों में से 98.3% जिलों में संघ की शाखाएं चल रही हैं। कुल 6,618 खंडों में से 92.3% खंडों (तालुका), कुल 58,939 मंडलों में से (मंडल माने 10–12 ग्रामों का एक समूह) 52.2% मंडलों में, 51710 स्थानों पर 83,129 दैनिक शाखाएं तथा अन्य 21936 स्थानों पर 22866 साप्ताहिक मिलन केंद्रों के माध्यम से संघ कार्य का देशव्यापी विस्तार हुआ है, जो लगातार बढ़ रहा है। इन 83129 दैनिक शाखाओं में से 59% शाखाएं छात्रों की हैं तथा शेष 41% व्यवसायी स्वयंसेवकों की शाखा में से 11% शाखाएं प्रौढ़ (40 वर्ष से ऊपर आयु) स्वयंसेवकों की हैं। बाकी सभी शाखाएं युवा व्यवसायी स्वयंसेवकों की हैं।

खेल आदि कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति निर्माण का जो कार्य संघ शाखा द्वारा चलता है, उसमें केवल पुरुष आते हैं। इसी कार्य हेतु महिलाओं के बीच राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से शाखाएं चल रही हैं। स्वयंसेवकों द्वारा प्रचार विभाग, संपर्क विभाग तथा सेवा विभाग के माध्यम से जो समाज जागरण के कार्य चल रहे हैं, उन सभी में महिलाओं का सहभाग है। यह सहभाग और बढ़े इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह, समाज परिवर्तन के कार्य में धर्म जागरण समन्वय, ग्राम–विकास, कुटुंब–प्रबोधन, सामाजिक समरसता, गौ–संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, घुमंतू कार्य तथा सामाजिक सद्भाव कार्य हेतु जहां–जहां स्वयंसेवक सक्रिय हैं, उनमें साथ मातृशक्ति और समाज की सज्जन शक्ति भी सक्रिय है तथा उनका सक्रिय सहभाग बढ़े, ऐसा संघ का आग्रह तथा प्रयास रहता है। एक राष्ट्रीय विचार को लेकर समाज–जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यवस्था परिवर्तन हेतु मजदूर, किसान, छात्र, विद्यालय, धार्मिक संत, राजनीति, कलाकार, अधिवक्ता, लघु उद्यमी, वनवासी बंधु, खेल आदि 35 विविध क्षेत्रों के माध्यम से स्वयंसेवक सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं। इन सभी कार्यों में महिला सहभाग बढ़े, इसके भी प्रयास चल रहे हैं। ये सभी कार्य, जिसमें स्वयंसेवक सक्रिय हैं, स्वतंत्र और स्वायत्त हैं। यह संघ की अवधारणा है और आचरण भी।

संघ की 100 वर्ष की यात्रा और लक्षणीय विस्तार आसान नहीं था। प्रथम उपेक्षा, बाद में उपहास, फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हर स्तर पर हर तरह से इसका विरोध हुआ। कहीं–कहीं तो संघर्ष भी हुए। पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण की

यात्रा अविरत चलती रही। कार्यकर्ताओं का परिश्रम, त्याग, बलिदान, समाज का सहयोग तथा ईश्वर के आशीर्वाद के बल पर 'संघ बढ़ता जा रहा है'। आज संघ कार्य में समाज का समर्थन और सहभाग भी बढ़ रहा है। समय–समय पर समान मुद्दों के आधार पर (issue based) समाज सहयोग भी कर रहा है। इस कारण संघ की शक्ति, प्रभाव के साथ समाज की मानसिकता में परिवर्तन अब दिखने लगा है।

संघ कार्यकर्ताओं का जोर विजयादशमी 2025 तक संघ कार्य की गति बढ़ाकर इसे और अधिक व्यापक बनाने पर रहा ताकि अधिकाधिक लोग संघ के सीधे संपर्क में आकर इसे समझ सकें और संघ से जुड़ सकें। 2025 के विजयदशमी के बाद स्वयंसेवक अधिक से अधिक लोगों को उनकी रुचि के अनुसार समाज परिवर्तन के पांच विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोगी बनाने के लिए सक्रिय हो रहे हैं। 'पंच परिवर्तन' के पांच विषय हैं– कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, स्वदेशी जीवन–शैली तथा लोक–कर्तव्य बोध।

संघ की यशस्वी विकास–यात्रा देख कर लोग अचंभित होते हैं, प्रशंसा करते हैं, अभिभूत होते दिखते हैं। इस सारी सफलता का श्रेय संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार के व्यक्तित्व, दर्शन और उनकी अमोघ कार्यपद्धति को जाता है। राजनीतिक सत्ता पर अवलंबित न रह कर समाज आधारित रचनाएं खड़ी करने के आग्रह के कारण समाज का यह परिवर्तन (transformation) शाश्वत परिणाम में परिवर्तित होता दिखता है। एक संघ गीत है–" केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस। जाग्रत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज।"

यह सब देखते और करते हुए एक मर्यादा भी ध्यान में आती है कि संपूर्ण समाज को यदि जाग्रत, संस्कारी, गुणवान तथा संगठित करना है, तो केवल शाखा का व्याप बढ़ाने से यह पूर्णत: साध्य नहीं होगा। इसके लिए समाज की स्वाभाविक व्यवस्थाएं जैसे परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय तथा समाज द्वारा ऐसे संस्कार देने की व्यवस्था करनी होगी। जब हर जगह, हर स्तर पर ऐसे अनुकरणीय उदाहरण (role models) दिखेंगे, तो उसे देखकर समाज के सभी लोग (बालक–बालिका, युवक–युवती) इस प्राचीन और विशिष्ट राष्ट्र की वास्तविक अवधारणा को समझेंगे और उसके अनुकूल आचरण और व्यवहार करेंगे, तभी संपूर्ण समाज में परिवर्तनकारी सकारात्मक शक्ति का निर्माण होगा। तभी समृद्ध, सशक्त और सक्रिय भारत अपनी सर्व समावेशी, एकात्म और सर्वांगीण सांस्कृतिक पहचान बना कर एक दीपस्तंभ के समान मानवता को मार्गदर्शन करने की स्थिति में आएगा और अपना वैश्विक दायित्व निभाने के लिए सक्षम, तत्पर होगा।

संघ की शाखाओं के माध्यम से तथा स्वयंसेवक अपने आचरण से जो राष्ट्र कार्य कर रहे हैं, वह समाज की स्वाभाविक व्यवस्थाओं के माध्यम से होना शुरू होगा। विजयशाली संगठित समाज निर्मित होगा, होते रहेगा और संपूर्ण समाज का कार्य बनकर, संघ कार्य चलता रहेगा।

□□□

विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का भारतीय मॉडल ही राष्ट्र-हित में स्वीकार्य

विज्ञान और तकनीक ने जीवन को सरल बनाया, लेकिन गंभीर समस्याएं भी पैदा की

प्रेरक पाथेय

डॉ. कृष्ण गोपाल

मान्य संपर्क अधिकारी- लघु उद्योग भारती एवं सह सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

(हरियाणा के समालखा खंड के पट्टी कल्याणा गाँव में सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र में आयोजित लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय उद्यमी सम्मेलन के अवसर पर देशभर के उद्यमियों को संबोधित किया)

नयी तकनीक के साथ नया रोजगार सृजन नहीं हो रहा-

विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को सरल बनाया, लेकिन गंभीर समस्याएं भी पैदा की। हर दिन नई तकनीक आ जाती है, और पहले से बाजार में चल रहे प्रोडक्ट को बंद करना पड़ जाता है। ग्लोबल मार्केट और विज्ञापन है लोग खरीदते हैं। इंडस्ट्रीज का केन्द्रीकरण कर दिया गया है, तो बाजार पर भी कुछ कंपनियां अपना आधिपत्य जमा लेती हैं। इससे दुनियाभर में केवल कुछेक घराने एसेट्स पर कब्जा कर रहे हैं, अधिकांश पूँजी गिने-चुने लोगों के पास सिमट कर रह जाती है, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। पूंजी और उद्योगों में लगातार हो रहा केंद्रीकरण गहरी चिंता का विषय है। अमेरिका करीब 32 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का देश है और आबादी 35 करोड़ के आसपास ही है। लेकिन बेरोजगारी तो वहां भी है, इसलिए इन समीकरणों को समझना पड़ेगा।

ज्यादा तकनीक से ज्यादा रोजगार बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज रोजगार के लिए हो रहे पलायन के कारण उत्तराखंड के गांव समाप्त हो गए। ये विकास का नहीं, विनाश का मॉडल है। भारत को ऐसे मॉडल की जरूरत नहीं।

विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था से पलायन पर लगेगी रोक-

शहरों की बड़ी आबादी जुग्गी-झोपड़ियों में रहने को अभिशप्त है और वहां उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान सब खत्म हो रही है। तो इसका समाधान क्या है? वास्तव में भारत के 7 लाख गावों और 140 करोड़ लोगों के जीवन को ध्यान में रखकर आर्थिक नीति बनाने की जरूरत है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर भारतीय आर्थिक परिवेश में विकेंद्रित अर्थव्यवस्था ही राष्ट्र के लिए हितकारी सिद्ध हो सकती है।

इससे करोड़ों भारतीयों के आर्थिक जीवन को न केवल संबल मिल सकेगा, बल्कि शहरों की ओर तेज गति से हो रहे पलायन पर भी अंकुश लगाया जा सकता है।

असंतुलित बुनियादी विकास में गांव पिछड़े-

लेकिन आज हो क्या रहा है, देश के केवल बीस शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकार अपने सारे संसाधनों को झोंक रही है, मुंबई, पूना, हैदराबाद, बेंगलुरु, गुड़गांव, जयपुर आदि इसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के कितने शहरों का विकास हो रहा है? और हमारे सात लाख गांवों के विकास के बारे में हमारे पास विजन नहीं है। इस गंभीर संकट से अगर कोई निकाल सकता है, तो वो है हमारे कुटीर और लघु उद्योग।

लोकल के लिए वोकल बनें-

करीब 6 करोड़ से अधिक की संख्या में ये देशभर में फैले हुए हैं और ये बर्तन, ताला, बास्केट, दरी और हमारे जीवन से जुडी सभी छोटी–बड़ी सभी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ऐसे उद्योग हों जिनमें 5–10–20 लोगों को आसपास ही काम मिल सके, जिससे व्यक्तियों का विस्थापन न हो। बड़ी मशीन नहीं चाहिए, बल्कि छोटी मशीनों से विकेन्द्रित विकास होना चाहिए। ये गुणवत्तापरक उत्पाद बनाते हैं, लेकिन बड़े ब्रांड नहीं बन पाते। इनके लिए ही कहा गया 'वोकल फॉर लोकल'।

प्रकृति का करें दोहन, शोषण नहीं-

देश में 47 प्रतिशत जमीन पर पर्याप्त पानी नहीं है, ये प्रकृति के अंधाधुंध शोषण और हमारे लालच की वजह से हो रहा है। पर्यावरण के प्रति हमारी ये अनदेखी भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। जो उपलब्ध जल है, उसे हम दूषित कर रहे हैं और जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसलिए हर खेत को पानी और हर हाथ को काम कैसे मिले, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे। इसलिए ऐसी जमीन पर कम पानी की फसलें योजनापूर्वक लेनी चाहिए। या वहां उद्योग स्थापित हों।

आईटीआई सेंटर्स को करें अपडेट-

लघु उद्योग भारती ने उद्योगों के विकास और उत्थान के लिए विविध उत्पाद समूह बनाये हैं जैसे टेक्सटाइल, स्टोन, स्टील आदि। लेकिन इन सभी निर्माण इकाइयों में कुशल कार्मिक भी चाहियें और उसके लिए आईटीआई जैसे संस्थाओं के पाठ्यक्रम को युगानुकूल यानी इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाने की आवश्यकता है। इससे उद्योगों को बदलती तकनीक के साथ स्किल्ड वर्क फोर्स की उपलब्धता भी हो सकेगी।

श्रमिकों के प्रति रहें संवेदनशील

एक और महत्वपूर्ण विषय है कि नियमों का पालन करना हमारी आदतों में शामिल होना चाहिए और हम इस बात को देखें कि हम हमारे उद्योग–व्यापार का कितनी प्रामाणिकता से संचालन करते हैं। मिलावट और गलत तरीकों से धन कमाने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमें हमारे आचरण में पवित्रता, शुचिता और सत्यनिष्ठा को अपनाने की जरूरत है। हमारे उद्योग में कार्यरत श्रमिक बंधुओं का हेल्थ कार्ड बनायें। समय–समय पर उनके स्वास्थ्य की जाँच हो, ये सुनिश्चित करें। खूब कमाएं, लेकिन मितव्ययी जीवन की ओर बढ़ें।

ईशावास्य उपनिषद में प्रसिद्ध सूत्र "त्येन त्यक्तेन भुंजीथा" का उल्लेख है जिसका अर्थ है कि हम त्याग के भाव से लौकिक वस्तुओं का उपभोग करें। यही भारत का मौलिक विचार भी है। □□□

जीएसटी कर सुधारों पर छत्तीसगढ़ में हुआ मंथन

नया रायपुर स्थित मंत्रालय भवन में Next-Gen 2.0 विषय पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री श्री ओ.पी। चौधरी, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने उम्मीद जताई कि Next-Gen 2.0 व्यापारियों के लिए राहत और सुधार की नई सौगात लेकर आएगा। साथ ही इससे कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाया जाएगा, जिससे छोटे एवं मध्यम व्यापारी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल व्यापार को गति देगी, अनुपालन को आसान बनाएगी और कर भार में राहत प्रदान करेगी। लघु उद्योग भारती की ओर से बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सिपी दुबे, महामंत्री श्री कैलाश चंद्रवंशी, श्री जितेंद्र चंद्राकर, श्री विक्रम सिंह एवं श्रीमती तूलिका पांडे भी उपस्थित रहे। □□□

प्राचीन भारत की आर्थिक समृद्धि के निहितार्थ

मंथन

प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा

ख्यात चिंतक एवं शिक्षाविद

समूह अध्यक्ष, (आयोजना व नियन्त्रण)

पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज,

उदयपुर (राज.)

साथ में डॉ. जया शर्मा

भारत अति प्राचीन काल से समृद्ध देश रहा है। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और सभ्यतागत उन्नति की दृष्टि से भारत विश्व में अग्रणी रहा है। ब्रिटिश आर्थिक इतिहास लेखक एंगस मेडिसिन सहित कई अनुसंधानों के अनुसार ईसा की परवर्ती पन्द्रह शताब्दियों अर्थात इस्वी वर्ष शून्य से 1500 ईस्वी तक विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का सर्वोच्च 35–40 प्रतिशत अंश रहा है। सीएन हर्किन के मतानुसार 17वीं सदी तक विश्व के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत व चीन का संयुक्त योगदान 60–70 प्रतिशत रहा है।

विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था-

एंगस मेडिसिन के अनुसार मुगलकालीन आर्थिक गतिरोध के बाद भी 1700 ईस्वी में विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 24.4 प्रतिशत था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के दौर में वह घटकर 1950 तक मात्र 4.2 प्रतिशत रह गया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जेफ्रे बिलियमसन की पुस्तक 'इण्डियाज डी–इण्डस्ट्रियलाइजेशन इन 18 एण्ड 19 सेन्चुरीज' के अनुसार वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में भारत का अंश जो 1750 में 25 प्रतिशत था, वह घट कर 1900 में 2 प्रतिशत तक आ गया और इग्लैण्ड का अंश जो 1700 में 2.9 प्रतिशत था, वो 1870 तक ही बढ़कर 9 प्रतिशत हो सका था। अकबर के साम्राज्य से पूरा दक्षिण, राजस्थान की रियासतें व पूर्व में आसाम आदि के बाहर होने पर भी 1600 में उसका राजस्व 9 करोड़ डॉलर तुल्य आंका गया था। ग्रेट ब्रिटेन का राजस्व 9 करोड़ डॉलर के स्तर पर 200 वर्ष बाद 1800 में ही पहुँच सका था। अरब आक्रान्ताओं, गुलाम वंश व मुगल काल में हुए शोषण, जजिया, सतत युद्ध रक्तपात के उपरान्त भी अंग्रेजों के आने तक, पाँच हजार वर्ष पूर्व महाभारत काल व उसके पूर्व सिन्धु घाटी सभ्यता वैदिक काल से चली आ रही समृद्धि बनी रही है।

भारत सम्पन्नता की दृष्टि मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग वंश व बाद तक भी विश्व में अग्रणी रहा है। वैदिक काल के कृषि, उद्योग व व्यापार के विवेचन अनादि काल से विगत 10 हजार वर्षों के उत्कृष्ट आर्थिक व सभ्यतागत उन्नति के द्योतक हैं। ऋग्वेद के शतरित्र अर्थात सौ प्रकोष्ठ युक्त जलयानों से सामुद्रिक व्यापार के सन्दर्भ इसके प्रमाण हैं।

सभ्यतागत उत्कर्ष-

सभ्यतागत उन्नति के अनगिनत सन्दर्भों में से यदि भगवान राम के अयोध्या पुनरागमन के अवसर पर राजा भरत को शत्रुघ्न सहित मन्त्रियों को सडकों पर बर्फ से ठण्डे किये जल के छिड़काव का उद्धरण उस सभ्यतागत चरम का संकेत करते हैं कि तब बर्फ से जल को शीतल कर सड़कों पर छिड़काव का प्रचलन रहा होगा, जिसकी आज विश्व के 200 देशों में कोई कल्पना भी नहीं करता है। हम आज कहते हैं कि भण्डार किए जाने योग्य बर्फ का उत्पादन 1858 से प्रारम्भ हुआ। लेकिन, तब अयोध्या में ऐसी भण्डारित बर्फ रही होगी जिससे तत्काल पानी को शीतल कर छिड़काव किया होगा।

वहाँ वाल्मीकि रामायण में शब्द हैं– "हिम शीतेन वारिणः" जिसका अर्थ यही होता है कि 'हिम' अर्थात बर्फ से 'शीतेन' अर्थात ठंडा किया हुआ और 'वारिणः' अर्थात जल। भारत की इसी प्राचीन समृद्धि के सम्बन्ध में उपलब्ध कुछ आर्थिक व पुरातात्विक अनुसंधान की संक्षिप्त समीक्षा यहाँ किया जाना समीचीन होगा।

एंगस मेडिसन कृत अनुसन्धान-

विश्व के सर्वाधिक ख्यातनाम व शीर्ष आर्थिक इतिहास लेखक एंगस मेडिसिन द्वारा औद्योगिक देशों के संगठन ओईसीडी के निर्देश पर, सुदीर्घ, श्रम–साध्य शोधों के बाद लिखी उनकी पुस्तक "विश्व का आर्थिक इतिहास– एक सहस्राब्दी–गत दृष्टिपात" वैश्विक आर्थिक इतिहास की सर्वाधिक प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स स्थित, औद्योगिक देशों के उक्त संगठन "आर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डवलपमेण्ट" जिसके अमेरिका, जापान व यूरोप के देश सदस्य हैं, के मुख्यालय से यह पुस्तक 2001 में प्रकाशित हुयी है। इस पुस्तक में एंगस मेडिसिन ने भारत, अपने तथ्य पूर्ण शोधों के आधार पर, को ईस्वी वर्ष 1 से 1500 तक विश्व का सबसे धनी देश सिद्ध किया है। देखें तालिका क्रमांक–1 में तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये हैं।

तालिका क्रमांक–1

शून्य एडी से बीसवीं सदी तक विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान

(क्रय सामर्थ्य साम्य के आधार पर 10 लाख डॉलर में सकल घरेलू उत्पाद)

देश/क्षेत्र	1	1000	1500	1600	1700	1820	1990
पश्चिमी यूरोप	14,433	10,925	44,183	65,602	81,213	159,851	367,466
पूर्वी यूरोप	1,956	2,600	6,696	9,289	11,393	24,906	50,163
रूस	1,560	2,840	8,458	11,426	16,196	37,678	83,646
यूएसए	272	520	800	600	527	12,548	98,374
लेटिन अमेरिकी देशों का योग	2,240	4,560	7,288	3,763	6,346	14,921	27,311
जपान	1,200	3,188	7,700	960	15,390	20,739	5,393
चीन	26,820	26,550	61,800	96,000	82,800	228,600	189,740
भारत	33,750	33,750	60,500	74,250	90,750	111,417	134,882
विश्व	105,402	120,379	248,445	331,562	371,428	694,598	1,110,951

ब्रिटिश आर्थिक इतिहास लेखक एंगस मेडिसिन की इस पुस्तक "वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ए मिलेनियम पर्सपेक्टिव" के अनुसार ईस्वी 1 से 1500 तक विश्व के सकल उत्पादन में भारत का योगदान 33 प्रतिशत था जो आज भिन्न–भिन्न आधारों पर गणना कर लेने पर भी मात्र 3 से 6.5 प्रतिशत तक आता है। मुगल अत्याचारों के लम्बे दौर के बाद 1700 ईस्वी तक भी विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत का अंश उन्होंने 22 प्रतिशत बताया है। लेकिन, आज इस अध्ययन के 20 वर्ष बाद भी हमारी इतिहास की पुस्तकों व अधिकांश अर्थशास्त्र की पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं है। दुर्भाग्य से ऐसे ख्यातनाम आर्थिक इतिहास लेखकों यथा एंगस मेडिसन आदि अनुसन्धानों से अनभिज्ञता के फलस्वरूप देश के पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने तो 2007 में अपनी पुस्तक 'एन आउटसाइड व्यू: व्हाई गुड इकोनॉमिक्स वर्क फॉर एवरीवन' के विमोचन के अवसर पर लखनऊ में आयोजित संगोष्ठी में यहाँ तक कह दिया था कि "भारत कभी भी धनी देश नहीं रहा है। देश में गरीबी सदा थी और आज भी है और भारत में घी–दूध की नदियों और इसके सोने की चिड़िया होने के मिथक पर आधारित पुस्तकों को जला देने की आवश्यकता है"। उनका यह कथन हास्यास्पद ही कहा जा सकता है।

हमारी उन्नत प्रौद्योगिकी, व्यापार व वाणिज्य के पुरावशेष-

पिछले 6–7 दशकों में हुए पुरातात्विक अनुसन्धानों पर दृष्टि डालें, तो हमारी प्राचीन प्रौद्योगिकी व उन्नत अर्थव्यवस्था के अनगिनत प्रमाण सामने आते हैं।

कोडुमानल 2500 वर्ष प्राचीन औद्योगिक नगर–

विगत 30 वर्षों में तमिलनाडु के कोडुमानल गांव के पुरातात्विक उत्खननों में 2500 वर्ष प्राचीन एक पूरे औद्योगिक नगर के अवशेष मिले हैं। इसमें अत्यंत उन्नत वस्त्रोद्योग, रत्न प्रविधेयन और विविध प्रकार के उत्कृष्ट इस्पात उत्पादन के प्रचुर प्रमाण मिले हैं। वहाँ पर 1500 वर्ष प्राचीन थाईलैंड, मिस्र व रोम के सिक्के भी निकले हैं। इससे उस काल में हमारे दक्षिण पूर्व एशिया, अरब व यूरोप तक होने वाले व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। आज की चमकदार अर्थात विट्रीफाईड टाईलों जैसे, विट्रीफाईड क्रूसिबल्स मिलने से यह भी सिद्ध होता है कि, आधुनिक विट्रीफिकेशन की प्रक्रिया का आविष्कार यूरोप में पिछली शताब्दी में न होकर 3 हजार वर्ष पूर्व भारत में ही हो चुका था और हम 2500 वर्ष पूर्व आज जैसा उत्कृष्ट स्पात या स्टील बनाने में सक्षम थे। कोडुमानल में मिले अनेक उत्तर भारत के नामपट्टों व अभिलेखों से लगता है कि 2500 वर्ष पूर्व देश में आर्य और द्रविड़ जैसा कोई विभाजन एवं उनमें किसी प्रकार का वैमनस्य भी नहीं था। इससे आर्यों के बाहर से आगमन व द्रविडों पर आक्रमण की कल्पना भी निराधार हो जाती है।

कोडुमानल के उत्खननों में पद्मासन की अवस्था में बैठे नर–कंकाल भी मिले हैं, जो वहाँ 2500 वर्ष पूर्व योग की परम्परा का प्रमाण देते हैं। हाल में किये वंशाणु साम्य अर्थात जीन पूल के अध्ययनों में उत्तर व दक्षिण भारत के लोगों में नस्ल भिन्नता के भी कोई प्रमाण सामने नहीं आते हैं। आर्यों के भारत के बाहर से आने व द्रविड़ों पर आक्रमण और उनके बीच परस्पर अलगाव का मिथक कोडूमनाम में उत्तर व दक्षिण भारत में पारस्परिक व्यापार व लेन–देन के प्रमाणों से भी निर्मूल हो जाता है।

वस्तुतः सिन्धु घाटी सभ्यता का आर्यों द्वारा भारत में आगमन पर नष्ट किये जाने के जो मनगढ़न्त यूरोपीय विमर्श हैं। वे तो अनगिनत नवीन खोजों में निर्मूल सिद्ध हो गये हैं। उपग्रह के चित्रों व नवीन पुरातात्विक उत्खननों से निर्विवाद रूप से यह सिद्ध हो गया है कि वह सभ्यता 300 वर्ष तक अनावृष्टि व

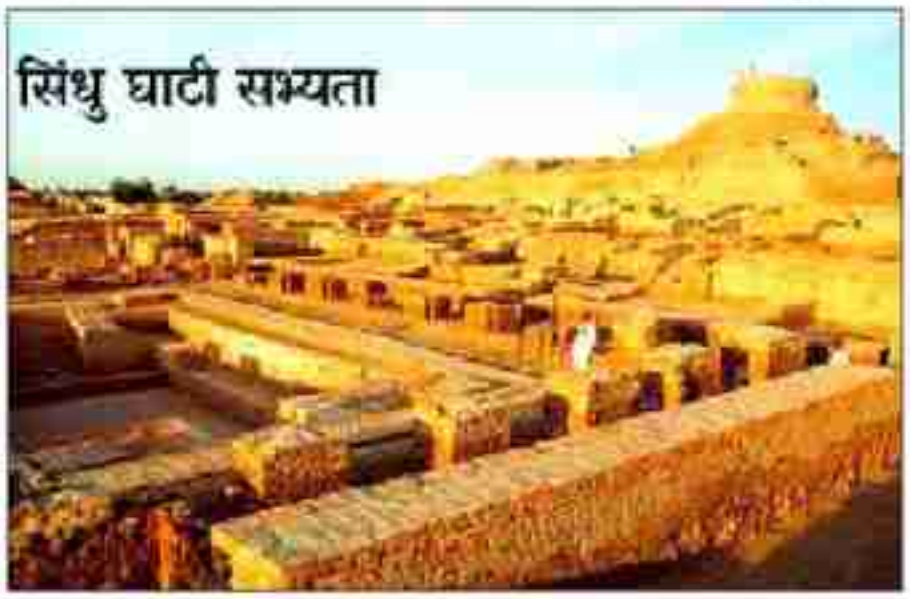

अनेक बार हुये जल प्लावन से समाप्त हुई है। सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया है कि वहाँ से कोई आक्रमण जनित विस्थापन नहीं हुआ, जैसा आर्यों के बाहर से आगमन की बात करने वाले इतिहासकार कहते आये हैं। विश्व के अति प्राचीन विश्वविद्यालयों में गिने जाने वाले 1575 में स्थापित लीडेन विश्वविद्यालय में तमिल के चोलराज राजेंद्र की राजाज्ञा का एक हजार वर्ष प्राचीन 30 किलो वजन का ताम्र–पत्र आज भी उपलब्ध है, वह राजाज्ञा–पत्र संस्कृत में विष्णु–स्तुति से प्रारम्भ होता है उसी में बाद के वर्णन तमिल भाषा में हैं। इससे यह मिथक भी ध्वस्त हो जाता है कि तमिलनाडु में पूर्वकाल में संस्कृत भाषा व विष्णु पूजा का चलन नहीं था। लीडेन विश्वविद्यालय ने 2014 में चोलराज के राज्यारोहण की सहस्त्राब्दी के उपलक्ष्य में उनका प्रदर्शन भी किया था। स्मरण रहे कि चोलराज राजेन्द्र ने एक हजार वर्ष पूर्व अपने राज्य का विस्तार बंगाल में गंगा तट से सम्पूर्ण श्रीलंका व म्यांमार सहित सम्पूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया तक किया था। लेकिन, इन सभी नवीन अनुसन्धानों का इतिहास की पुस्तकों में समावेश न होना चिंताजनक है।

प्राचीन बन्दरगाह-

द्वापर युग के अंत में 5245 वर्ष पूर्व श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था, उन्हीं श्री कृष्ण की द्वारिका के पुरातात्विक अवशेष आज समुद्र में 120 फीट नीचे जल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनेग्राफी ने खोज लिये हैं। वे रेडियो कार्बन काल निर्धारण प्रक्रिया में 5000 वर्ष पुराने सिद्ध हुए हैं। उनमें प्राचीन द्वारिका की समुद्र से रक्षार्थ बनाई 30 फीट चौड़ी शहरकोट (नगर रक्षा प्राचीर) के अवशेष और उस समय के भवनों, बरतनों आदि के महत्त्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, जो 5000 वर्ष पुराने सिद्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ खंभात में 7500 वर्ष प्राचीन बंदरगाह के भी अवशेष मिले हैं, जिनमें जहाजों के लिए 150 से अधिक लंगर, बंदरगाह की जेटी आदि प्रमुख हैं।

स्वाधीनता के समय की समृद्धि पर समाजवादी ग्रहण-

स्वाधीनता के समय 1947–48 में भी भारत की अर्थव्यवस्था का अंतर्निहित सामर्थ्य, तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा था। तब 1947 में 1 डॉलर मात्र 3.50 रुपए तुल्य था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी समाजवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु 1949 में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापनार्थ, विश्व बैंक से ऋण लेने के लिए रुपये का अवमूल्यन किया गया।

इसके बाद 1966 में श्रीमती गाँधी व 1991 में डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा बड़े अवमूल्यन किए गये। हमारी मुद्रा के अवमूल्यन के कारण ही आज रुपए का मूल्य प्रति डॉलर 70–75 रुपए तक गिरा है। ऐसे अवमूल्यन नहीं किए जाते, तो आज हमें 1947 की विनिमय दर पर 100 डॉलर के खनिज तेल के आयात पर 350 रुपए ही खर्च करने होते व वहीं अवमूल्यन के कारण आज 100 डॉलर के आयात पर 7500 रुपए व्यय करने पड़ते हैं। स्वाधीनता के समय 1947 में हमारा इंग्लैण्ड पर 1400 करोड़ रुपयों का पाउण्ड स्टार्लिंग में कर्ज था, जिसे वह तब चुकाने मे सक्षम नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध में उसकी अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई थी। इसलिए इंग्लैण्ड ऋणी था व हम ऋणदाता थे। विश्व बैंक व मुद्रा कोष की स्थापना के समय से 1958 तक हम इन दोनों के पांच सबसे बड़े अंशधारियों में एक थे और 1963 तक हमारा एक–एक स्थायी निदेशक विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों के संचालक मंडल में रहा है।

नेहरू–इन्दिरा युग की समाजवादी नीतियों एवं 1991 मे आयात उदारीकरण और विदेशी निवेश प्रोत्साहन जैसी कई परावलम्बनकारी नीतियों के बाद प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत व स्वदेशी का महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित कर, अर्थव्यवस्था को गतिमान करने की ओर कदम बढ़ाने आरम्भ किए हैं। □□□

INDIA INDUSTRIAL FAIR 2025

औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में भारत उद्योग दर्शन का सफल आयोजन

विशिष्ट प्रतिभाएं 'भिवाड़ी गौरव अवार्ड' से सम्मानित

बी2बी एग्जिबिशन में 327 स्टॉल्स पर उत्पाद प्रदर्शित

उद्योग प्रदर्शनी

डॉ. संजय मिश्रा

को-एडिटर, उद्योग टाइम्स

dr.sanjay.jpr@gmail.com

लघु उद्योग भारती राजस्थान की भिवाड़ी की पांचों इकाइयों द्वारा आयोजित तीन दिवसीय IIF-2025 (इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर) 19 सितम्बर को मेला ग्राउंड पर विघ्नहरता श्री गणेश की विधिवत पूजा–अर्चना से प्रारम्भ हुआ। उद्घाटन अवसर पर लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, तिजारा विधायक श्री महंत बालकनाथ, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सीए श्री योगेश गौतम, एलयूबी राष्ट्रीय सचिव श्री नरेश पारीक, प्रदेश महासचिव श्री सुधीर गर्ग, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता, जयपुर अंचल अध्यक्ष श्री महेंद्र मिश्रा, उपाध्यक्ष श्री रामप्रकाश गर्ग एवं सचिव सुश्री सुनीता शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस ट्रेड फेयर में मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेट्रॉनिक्स, पैकेजिंग आदि उत्पाद प्रदर्शित किए गए। जिला उद्योग केंद्र ने ओडीओपी स्कीम में 30 स्टॉल भी लगाए।

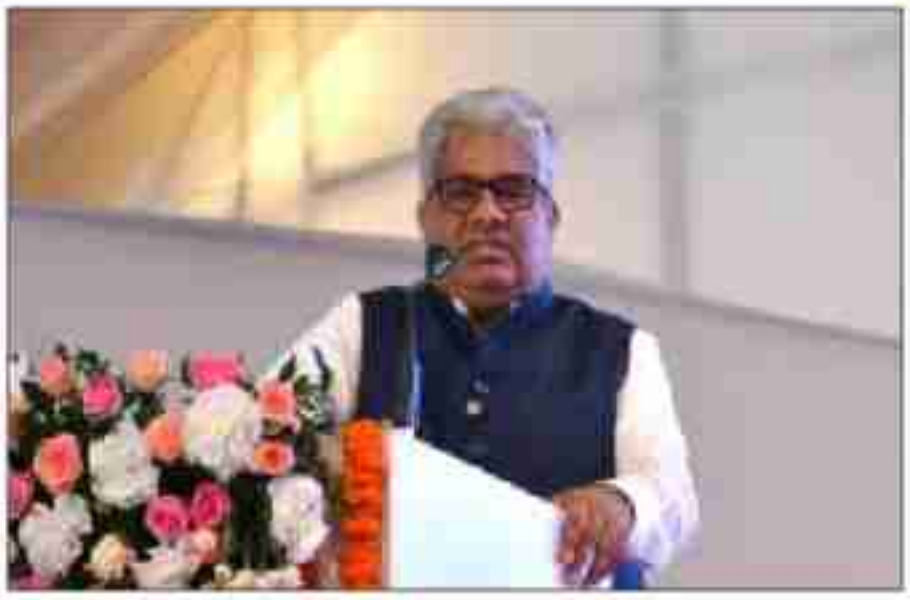

उद्घाटन सत्र-

चरखे से चंद्रमा तक छाया हुआ है स्वदेशी, आत्मनिर्भरता का यही मंत्र-

मुख्य अतिथि एवं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विकसित भारत के लिए स्वदेशी को साकार करना होगा। स्वदेशी के मायने केवल चरखा और स्थानिक हस्तशिल्प ही नहीं है, बल्कि भारतीय स्वदेशी चरखे से लेकर अब चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। श्री यादव ने कहा कि कोविड महामारी के वक्त स्वदेशी वैक्सीन ने ही 140 करोड़ लोगों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की और उस कठिन दौर में भी मोदी सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाया। आज आर्थिक दृष्टि से भारत ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर पांचवे पायदान पर जगह बनाई है। उन्होंने बताया कि देश में कुल 67 की संख्या में एयरपोर्ट थे जो अब 167 हो गये हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर की गति ऐसी है कि अब आने वाले दिनों में एनएच 8 और एक्सप्रेस–वे को भी जोड़ने की तैयारी है।

उद्यमी निर्भीकता से उद्योग चलाएं, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी-

श्री यादव ने बताया कि फॉरेस्ट एरिया में प्लांटेशन के जरिए ग्रीन क्रेडिट पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही उद्योगों में एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए नई ऑडिट व्यवस्था को शुरू किया जाएगा जिससे उद्यमी निर्भीकता से अपने उद्योग चला सकेंगे। इससे इंस्पेक्टर राज से मुक्ति भी मिलेगी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म में जिन दो स्लैब में सभी प्रोडक्ट्स को रखा, उससे खेती में काम आने वाले ट्रैक्टर 70 हजार, कार 20 हजार रुपए तक सस्ते होंगे। इसी तरह इलेट्रॉनिक्स के दैनिक उपयोग के सामान भी पहले से कम कीमत पर मिलेंगे।

श्री यादव ने कहा कि सरकार इज ऑफ डूइंग और लीविंग बिजनेस में विश्वास करती है। उन्होंने भिवाड़ी डेवलेपमेंट ऑथोरिटी के गठन, स्वच्छ भिवाड़ी के लिए जल भराव की समस्या का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 108 ई–लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है जिससे 20 हजार बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया गया।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के उद्योगों के लिए स्किल्ड वर्क फोर्स उपलब्ध करवाने के लिए स्किल डेवलेपमेंट सेंटर के लिए सरकार ने बजट पारित किया है। इस केंद्र में लघु उद्योग भारती संगठन नोडल एजेंसी के रूप में इसका संचालन करेगा। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलेपमेंट से लघु उद्योगों के विकास में असीम ऊर्जा का संचार कर रहा है।

उत्कृष्ट निर्माण परंपरा भारत की पहचान–

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र ने बताया कि उद्यमिता और उत्कृष्ट निर्माण परंपरा भारत की हजारों वर्षों की पहचान रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने अपने हाथों के हुनर से भारत को समृद्ध बनाया, किसी को लूटकर नहीं।

संगठन महामंत्री ने बताया कि अंग्रेजों के समय की पराधीनता के कारण हम पहली तीन औद्योगिक क्रांति में विशेष कुछ नहीं कर पाए, लेकिन चौथी औद्योगिक क्रांति में हमने बहुत प्रगति की।

श्री प्रकाशचंद्र ने कहा कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी तक अंग्रेजियत बची हुई है, उससे हमारे मौलिक भारत को बचाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि बदलती विश्व राजनीति और आर्थिक परिस्थितियों के कारण हमें मिलकर काम करना होगा। कंसोर्टियम बनाने होंगे, अकेले या अलग थलग पड़े रहकर आगे नहीं बढ़ सकते हमारे लघु उद्योग। उन्होंने बताया कि जिन उत्पादों को हम आयात करते है, उसे हम यहां निर्माण करें, वोकल फॉर लोकल पर कार्य करने की जरूरत है। इसी तरह एक्सपोर्ट में प्रमोशन करने के लिए हमें गुणवत्तापरक उत्पाद बनाने होंगे।

बानसूर विधायक श्री देवीसिंह शेखावत ने बताया कि लघु उद्योग भारती ने उद्यमियों की समस्याओं को हल करने में बड़ा योगदान किया है। उन्होंने कहा कि डेयरी उद्योग के लिए ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है।

तिजारा से विधायक श्री बाबा बालकनाथ ने कहा कि इस तरह के ट्रेड फेयर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में ये आयोजन उद्योगों की गति को बढ़ाएगा।

लघु उद्योग भारती के संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव श्री नरेश पारीक ने जानकारी दी कि लघु उद्योग भारती संगठन बीते 31 वर्षों से लघु उद्योगों के उत्थान में कार्य कर रहा है जो देशभर में 587 जिलों में 1062 इकाइयों के साथ करीब 62 हजार सदस्यों का विशाल नेटवर्क बन चुका है।

इससे पूर्व कॉर्डिनेटर **श्री एलएन गुप्ता** ने आईआईएफ आयोजन के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। भारत उद्योग दर्शन प्रदर्शनी के सह संयोजक श्री (सीए) आर के गुप्ता ने आभार प्रदर्शित किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत मेला ग्राउंड पर लगी नमो प्रदर्शनी का अवलोकन भी अतिथियों ने किया।

प्रथम तकनीकी सत्र -

ओवरव्यू ऑफ वेंडर अप्रूवल सिस्टम विषयक तकनीकी सत्र

में आरडीएसओ लखनऊ से श्री अतुल सक्सेना और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज के श्री अशोक चौधरी ने रेलवे में वेंडर डेवलेपमेंट और टेंडरिंग की प्रक्रिया को समझाया। श्री संजय खन्ना ने इस सत्र को कोऑर्डिनेट किया। सत्र में लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती अंजू बजाज ने भी सहभागिता की।

द्वितीय तकनीकी सत्र

एंपावरिंग एमएसएमई- जीएसटी, आईपीओ एंड सब्सिडी इनसाइट्स विषयक तकनीकी सत्र में सीए योगेश गौतम, सीए यशस्वी शर्मा, सीए अर्पित मित्तल और सीए अक्षिमा यादव ने एंटरप्रेन्योर्स को उपयोगी जानकारी साझा की। इन सत्रों में लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती अंजू बजाज ने अध्यक्षता की। श्री कुणाल सिंह सहाय ने इस सत्र को कोऑर्डिनेट किया। इस अवसर पर अलवर जिला प्रमुख श्री बलबीर छिल्लर सहित में उद्यमीगण उपस्थित रहे।

द्वितीय दिवस, 20 सितंबर - तृतीय तकनीकी सत्र

आईआईएफ–2025 के दूसरे दिन **रोल ऑफ बैंक इन स्ट्रेंथिंग एमएसएमई** विषयक सत्र को सीए आरके गुप्ता ने

कोऑर्डिनेट किया। पीएनबी के जोनल हेड श्री राजेश भौमिक ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक ने राजस्थान सरकार के साथ 21 हजार करोड़ का एमओयू साइन किया। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में भी बताया। पीएनबी भिवाड़ी ब्रांच के हेड श्री प्रदीप कुमार उद्यमियों के लिए कई योजनाओं की जानकारी साझा की।

चतुर्थ तकनीकी सत्र

डिफेंस आरएंडडी इकोसिस्टम एंड डीआरडीओ - इंडस्ट्री पार्टनरशिप सत्र को श्री नितिन कोहली ने कोऑर्डिनेट किया। सत्र में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्गेनाईजेशन (डीआरडीओ) की सेल डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री इंटरफेस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के वैज्ञानिक श्री संजीव कुमार ने एमएसएमई के लिए इस क्षेत्र में अपार सम्भावना के बारे में बताया।

पंचम तकनीकी सत्र

ओवरव्यू ऑफ एनपीएल, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर, रीसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट प्लास्टिक फॉर स्ट्रक्चर फॉर सोसाइटल यूज विषयक तकनीकी सत्र को श्री विरल महिपाल गर्ग ने कोऑर्डिनेट किया। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ. राजीव सिंह ने बताया

कि देश की औद्योगिक समस्याओं का समाधान खोजने और आम जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सीएसआईआर की स्थापना हुई थी। डॉ. सिंह ने जानकारी दी कि संस्थान ने 2016 से प्लास्टिक पॉल्यूशन पर कार्य शुरू किया। फ्लाई एश और प्लास्टिक वेस्ट को साथ लेकर बायो टॉयलेट, फुटपाथ और सड़क के लिए पैनल्स बनाने का काम किया गया।

लेवरेंजिंग सीएसआईआर टेक्नोलॉजीज फॉर बिजनेस ग्रोथ-एन एंटरप्रिन्योर्स जर्नी में लघु उद्योग भारती और सीएसआईआर के संयुक्त प्रोजेक्ट 100 डेज–100 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत तकनीक लेने वाले दिल्ली के उद्यमी श्री नीरज सहगल ने अपने अनुभव और अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताया। इस सत्र में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री कवीन्द्र जुल्का ने भी सहभागिता की।

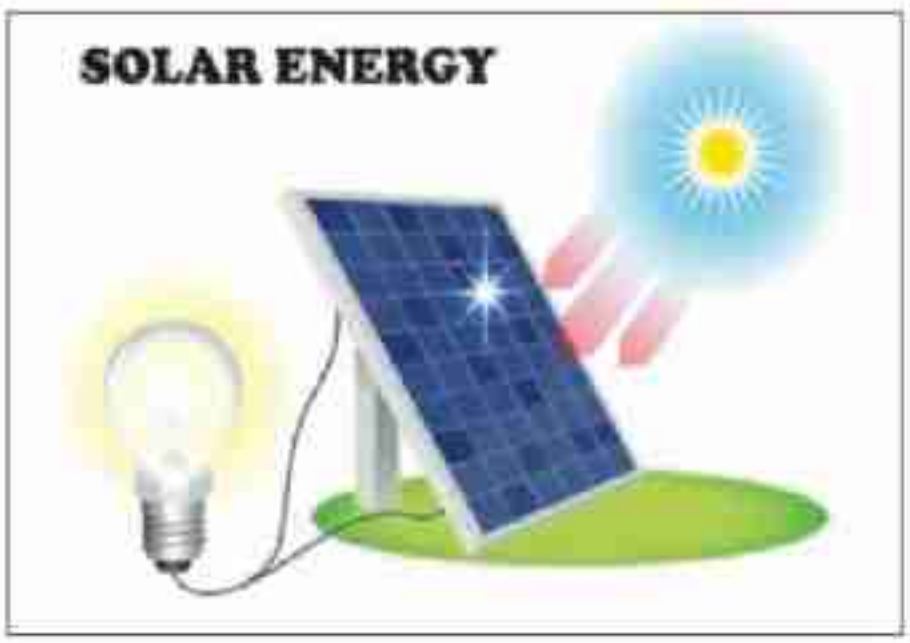

षष्ठम तकनीकी सत्र

सोलर एंड प्रअॅफिटेबिलिटी विषयक तकनीकी सत्र को चौपानकी इकाई संरक्षक श्री मुकेश शर्मा ने कोऑर्डिनेट किया। रेज पावर के श्री राहुल गुप्ता ने सोलर पावर प्रोजेक्ट के बिजनेस मॉड्यूल पर चर्चा की।

सप्तम तकनीकी सत्र

वेस्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी विषयक तकनीकी सत्र को वरिष्ठ उद्यमी श्री रामप्रकाश गर्ग ने कोऑर्डिनेट किया। दिल्ली की डॉ. रूबी माखीजा ने बताया कि प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स हमारे शरीर में लगातार इकट्ठे होकर कई जानलेवा बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकेले दिल्ली शहर से साढ़े ग्यारह हजार टन कचरा रोज पैदा होता है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट भी बड़ी मात्रा में रहता है। उन्होंने बताया कि हमारी घोर लापरवाही की वजह से कूड़े के बड़े अंबार देशभर में कई शहरों में लग गए हैं। उन्होंने सूखे, गीले और सेनेटरी वेस्ट को अलग रखने पर जोर दिया जिससे वेस्ट सौ फीसद रिसाइक्लिंग प्रोसेस में काम आ सके।

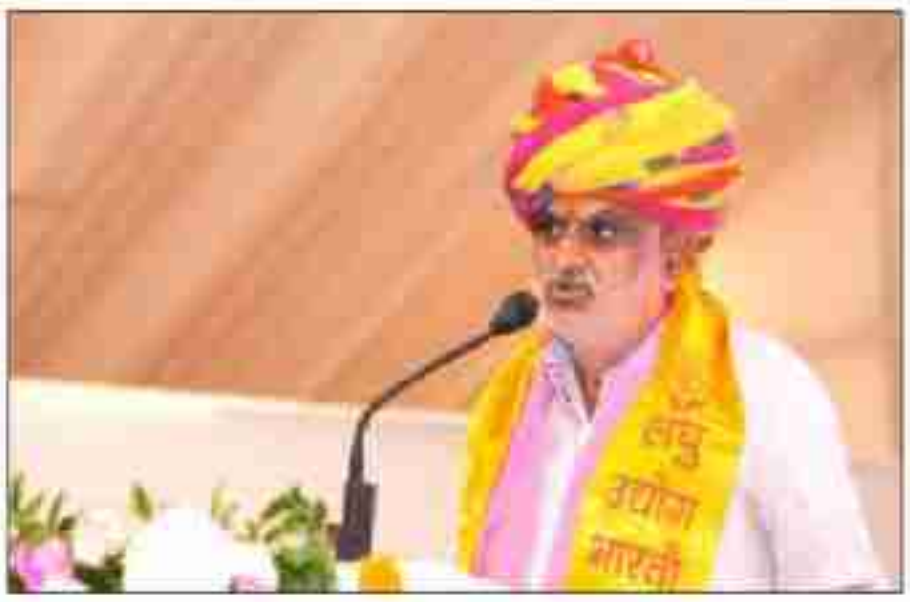

देश की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और उचित मंच देने की जरूरत- खर्रा

राजस्थान सरकार के नगरीय विकास मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के दूसरे दिन भिवाड़ी गौरव सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में देश की प्रतिभाओं को भरपूर प्रोत्साहन और उचित मंच देने की जरूरत है जिससे वे तकनीक और नवाचार के बल पर यहाँ के उद्योगों के विकास के साथ बेहतर उत्पादों का निर्माण और उसे निर्यात कर देश

की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान भी कर सकें।

उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों की तरक्की में भारत की उन प्रतिभाओं का भी पूरा योगदान रहा है जो किसी खास कारण से यहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद विदेशी धरती पर अपने करियर को बनाने के लिए गए। लेकिन बहुत से प्रतिभाशाली युवा वापस अपनी मातृभूमि पर आएं हैं और अपने प्रयासों, नवाचार और उद्यमिता से सफलता की नई कहानियां लिख रहे हैं।

श्री खर्रा ने कहा कि बहुत से उत्पादों में भारत की विदेशों पर निर्भरता कम हुई है, जबकि रक्षा क्षेत्र में तेजस जैसे लडाकू विमान को लेने के लिए कई देशों में होड मची हुई है। और ये बदलाव डिफेंस और तकनीक में हमारी बढ़ती हुई

आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती प्रदेश में कौशल विकास के प्रकल्पों से हमारे उद्योगों के लिए कुशल कार्मिकों का निर्माण कर रहा है।

उद्योग राज्य मंत्री श्री केके विश्नोई ने कहा कि पहले वर्ष में सरकार ने राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित कर साहस का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि चार लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर साकार भी हो गए हैं और अन्य सभी एमओयू पर काम चल रहा है। श्री विश्नोई ने बताया कि 11 दिसंबर को सरकार अपना निवेश का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष रखेगी।

उन्होंने कहा कि सत्तर के दशक में जब यहां उद्योगों की स्थापना शुरू हुई, तो किसी ने सोचा नहीं था कि भिवाडी प्रदेश का इंडस्ट्री हब भी बनेगा। श्री विश्नोई ने कहा कि पचपदरा की आधुनिक रिफाइनरी की शुरुआत भी जल्द होने जा रही है जिसका फायदा सभी उद्यमी उठाएं। उन्होंने लघु उद्योग भारती को सरकार और उद्यमियों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बताया जो उद्योगों के संरक्षण के लिए निरंतर सक्रिय है।

तिजारा विधायक श्री बाबा बालकनाथ ने कहा कि राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का विकास होना चाहिए। बहरोड़ विधायक श्री जसवंत यादव ने कहा कि लघु उद्योग भारती देश में उद्योग हितैषी नीतियों के निर्माण में कार्यरत है।

कामधेनु ग्रुप के सीएमडी श्री सतीश अग्रवाल ने बताया कि भिवाड़ी की औद्योगिक विकास यात्रा में उल्लेखनीय योगदान करने वाले उद्यमियों और विशेष उपलब्धियां अर्जित करने वाले विशिष्ट व्यक्तित्वों को भिवाड़ी गौरव सम्मान प्रदान कर लघु उद्योग भारती ने प्रेरणादायी की पहल है।

जयपुर प्रांत सचिव सुश्री सुनीता शर्मा ने लघु उद्योग भारती का औपचारिक परिचय दिया। राष्ट्रीय सचिव श्रीमती अंजू सिंह ने आईआईएफ और स्वयंसिद्धा जैसे आयोजनों के बारे में जानकारी दी। इससे पहले आईआईएफ के कन्वीनर श्री रामप्रकाश गर्ग ने भिवाड़ी गौरव सम्मान की आधारभूमि के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल असोसिएशन के अध्यक्ष एवं अग्रणी उद्यमी श्री प्रवीण लाम्बा सहित बड़ी संख्या में उद्यमीगण उपस्थित रहे।

'भिवाड़ी गौरव अवार्ड' से सम्मानित विशिष्ट प्रतिभाएं-

जापानी मार्शल आर्ट कूडो में सिल्वर मेडलिस्ट सुश्री आराध्या राव, राष्ट्रपति शिक्षक अवॉर्डी श्रीमती नीलम यादव, पहली महिला फाइटर पायलट श्रीमती शिवांशी पाठक, मॉडर्न पब्लिक स्कूल संस्थापक श्री सतीश कौरा, लायंस क्लब के श्री मृत्युंजय पांडे,रोटरी क्लब के श्री आरसी जैन, भारत विकास परिषद के श्री एच आर शर्मा, आशियाना हाउसिंग ग्रुप के श्री विशाल गुप्ता, आईएमए से डॉ। अजय गोयल, किनाकि मेडिलिक्स से श्री कीर्ति मेहता, ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी से श्री अनूप अरोड़ा, जय सर्जिकल्स के श्रीपंकज खेर, मेहरु इलेक्ट्रिकल्स के श्री संदीप शर्मा, साइरा इलेक्ट्रिक ऑटो के श्री विजय कपूर, वेल्स एयरकॉन के श्री विजयानंद, वेक्सी लिमिटेड से श्री राजेश सोनी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज से श्री जोगेंद्र बिष्ट, डॉ। ओटकर इंडिया के श्री जैनेन्द्र जीत सिंह, होंडा कार्स इंडिया से श्री रविंद्र सिंह, जक्वार एंड कं। से श्री बीबी दुग्गल, केईआई इंडस्ट्रीज के श्री गोविंद शर्मा, कामधेनु लि। के श्री सतीश अग्रवाल, श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स के श्री सुमंत्र मुखर्जी को उनकी उल्लेखनीय उद्यमशीलता और उपलब्धियों के लिए सम्मानितकिया गया।

- **समापन सत्र, 21 सितंबर**

औद्योगिक प्रदर्शनी युवाओं में उद्यमिता का बीज बोती हैं

मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा ने कहा कि औद्योगिक प्रदर्शनी युवाओं में उद्यमिता का बीज बोने का काम करती हैं और नए उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों की सार्थकता तब और बढ़ जाएगी, जब किसान के द्वारा उद्योगों के लिए दी गई जमीन पर लगने वाले कल-कारखानों में उसके बच्चों को भी रोजगार मिलेगा।

नॉन ट्रीटेड वाटर से जमीन को प्रदूषित न करें उद्यमी-

उन्होंने कहा कि उद्योगों का संचालन करते वक्त उद्यमी ट्रीटेड वाटर को पुनः काम में लेना सुनिश्चित करे। जो उद्योग ऐसा कर रहे हैं, वे निश्चित रूप से देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो उद्योग नॉन ट्रीटेड वाटर को सीधे जमीन पर छोड़ कर खतरनाक रसायनों के माध्यम से इस धरती को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं और पर्यावरण का सीधे नुकसान कर रहे हैं, ऐसे उद्योगों के विरुद्ध शासन की ओर से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री शर्मा ने जानकारी दी कि प्रदेश के जोधपुर बालोतरा के आवासीय क्षेत्र में संचालित ऐसे अनेक उद्योगों को सरकार ने बंद करवाया है जो बिना एनओसी के चल रहे थे और ये दूषित पानी से जमीन को नुकसान भी पहुंचा रहे थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में कभी ऐसी नौबत न आए, इसका हम सभी को ध्यान रखना होगा।

इस अवसर पर उन्होंने लघु उद्योग भारती द्वारा प्रदेश में कौशल विकास के जरिए महिला स्वावलंबन और स्वरोजगार

की दिशा में किए जा रहे अनूठे कार्यों की प्रशंसा की और बताया कि संगठन ने पारंपरिक कुटीर उद्योगों के संरक्षण के लिए भी विशेष प्रयास किए हैं।

इस अवसर पर तिजारा विधायक श्री बाबा बालकनाथ, रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह, श्री विमल पंडित और लघु उद्योग भारती जयपुर अंचल की सचिव श्री सुनीता शर्मा ने भी उद्यमियों को संबोधित किया। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को आसान ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सिडबी के प्रतिनिधि ने भी एमएसएमई की कई योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन श्री शशिकांत पाठक, श्रीमती अर्चना नाकरा, श्री नितिन रस्तोगी और श्रीमती नवनीता शर्मा ने किया। आईआईएफ टीम से श्री अनन्य जैन ने आभार प्रदर्शित किया।

लघु उद्योग भारती के प्रदेश महामंत्री श्री सुधीर गर्ग ने उद्योग प्रदर्शनी को सफल बताया। प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता ने कहा कि इस आयोजन से भिवाड़ी और आसपास के अन्य औद्योगिक क्षेत्र फोकस में आ गए हैं, जिससे यहां की बुनियादी समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो सकेगा और उद्योगों को भी और गति मिल सकेगी।

टीम भिवाड़ी के सक्रिय सहयोगी

आईआईएफ–2025 के सफल आयोजन के लिए टीम भिवाड़ी ने जयपुर अंचल उपाध्यक्ष श्री रामप्रकाश गर्ग, मुख्य समन्वयक श्री एलएन गुप्ता और सह समन्वयक सीए श्री आरके गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन में कार्य किया। ग्राउंड लेवल कोआर्डिनेशन में भिवाड़ी यूनिट–1 अध्यक्ष श्री सरजीत यादव, चौपानकी इकाई संरक्षक श्री मुकेश शर्मा और अध्यक्ष श्री विमल पंडित, यूनिट–2 सचिव श्री अजीत यादव, श्री नितिन जैन, श्री नितिन कोहली, श्री डीके शर्मा, श्री राजेश द्विवेदी, वेंडर डेवलपमेंट एंड सेमिनार में श्री संजय खन्ना, स्टेज मैनेजमेंट में श्री नितिन रस्तोगी और महिला इकाई अध्यक्ष श्रीमती मीना जैन ने सक्रिय सहयोग किया।

सफल आयोजन के सारथी–

आईआईएफ–2025 को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिये भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को स्टॉल के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया। इसी तरह भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से श्री प्रवीण लाम्बा एवं सीए बीएम अग्रवाल ने वित्तीय संसाधनों को जुटाने में विशेष सहयोग किया।

IIF-2025 के प्रायोजक– सिडबी, जिला उद्योग केंद्र, जैक्वार लिमिटेड, रेज एक्सपर्ट्स, एसबीएफ इस्पात लि., कामधेनु इस्पात लि. श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लि. एवं पंजाब नेशनल बैंक।

दुनिया में राजस्थानी मिट्टी की खुशबू फैला रहे प्रवासी

हैदराबाद प्रवासी राजस्थानी मीट में निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा

10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस होगा आयोजित

राजस्थान विशेष

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी जहां भी जाते हैं वहां अपनी संस्कृति, विचार और राजस्थानी मिट्टी की खुशबू बिखेरते हैं। दुनियाभर में प्रवासी राजस्थानी अपने काम के साथ सामाजिक सरोकार के कार्यों में भी बढ़–चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अनेक अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से अपील करते हुए कहा कि राज्य में उपलब्ध असीमित अवसरों में निवेश कर वे प्रदेश के विकास में साझेदार बनें जिससे एक नए तथा विकसित राजस्थान का निर्माण हो। श्री शर्मा 26 सितंबर को हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में इस साल10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रवासी राजस्थानियों को इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। श्री शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस की श्रृंखला की शुरुआत हैदराबाद से की गईहै। आगे भी देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की मीट आयोजित की जाएगी जिससे देश और दुनिया में मौजूद प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूती मिले।

प्रवासी राजस्थानियों के लिए बनेगा विशेष विभाग–

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य और जल संचयन जैसे क्षेत्रों के लिए विभिन्न सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर साल प्रवासी राजस्थानी सम्मान देगी और विभिन्न अवसरों पर भी सराहनीय कार्य करने वाले प्रवासियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के व्यावसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग के लिए एक विशेष विभाग का गठन किया जाएगा।

प्रवासी राजस्थानियों के लिए हर जिले में बना सिंगल प्वॉइंट कॉन्टेक्ट-

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान फाउंडेशन को सुदृढ़ किया है। इसके तहत पिछले एक साल में 14 नए चैप्टर खोले गए हैं तथा पूर्व के 12 चैप्टर्स में भी अध्यक्षों को मनोनीत कर सभी 26 चैप्टर्स को क्रियाशील किया गया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के न्यूयॉर्क, लंदन, रियाद जैसे

कई बड़े शहरों में राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर सुचारु रूप से चल रहे हैं और इनके जरिए प्रवासी समुदाय राज्य सरकार के साथ राजस्थान की विकास यात्रा के साझेदार बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के परिवारजन के लिए प्रदेश के हर जिले में सिंगल प्वॉइंट कॉन्टेक्ट बनाया गया है तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला कलक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं-

श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। राइजिंग समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए। अब तक लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतर भी चुके हैं। हम राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य देश में मौजूदा हाईवेज का तीसरा एवं रेलवे का पांचवां सबसे बड़ा नेटवर्क है। राजस्थान में सात प्रमुख हवाई अड्डे हैं और दिल्ली–मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे प्रदेश से गुजरता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए 20 से ज्यादा नई नीतियां बनाई गई हैं। साथ ही, कई नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। पचपदरा के रिफाइनरी भी इसी वर्ष शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1 हजार 232 निवेशकों को भूमि उपलब्ध करवाई गई है तथा 17 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 34 हजार हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है जो निवेश को धरातल पर उतारने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है।

ऊर्जा-पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार ले रही अभूतपूर्व निर्णय-

मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 सितंबर को ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के माही–बांसवाड़ा में 2 हजार 800 मेगावाट क्षमता की 42 हजार करोड़ रुपए लागत वाली न्यूक्लियर पावर परियोजना का शिलान्यास किया है। बैटरी स्टोरेज, पंप स्टारेज, रूफटॉप सोलर, पीएम कुसुम के तहत विकेंद्रीकृत सोलर प्रोजेक्ट सहित ऊर्जा के हर क्षेत्र में राज्य ने एक नई पहल की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में प्रतिवर्ष करोड़ों देशी–विदेशी पर्यटक आते हैं। राजस्थान का हर कोना, अपनी समृद्ध धरोहर, प्रकृति, संस्कृति और विविधताओं का दर्शन करवाता है। पर्यटन निवेश में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने भूमि आवंटन हेतु न्यूनतम निवेश को 100 करोड़ रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया है। इस संशोधन से हेरिटेज, वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के साथ–साथ घरेलू निवेशकों को भागीदारी का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने रिप्स–2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इन्सेंटिव के लिए पर्यटन में निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दी है।

श्री शर्मा ने प्रदेश में खनन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान खनिज नीति तथा राजस्थान एम–सैंड पॉलिसी लॉन्च की है। साथ ही, खनिजों के ब्लॉकों की नीलामी में अभूतपूर्व तेजी आई है। उन्होंने कहा कि जयपुर और जोधपुर में अत्याधुनिक टियर–4 डाटा सेंटर स्थापित किए गए हैं तथा शीघ्र ही नई सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी आने वाली है। प्रदेश में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, वस्त्र, चिकित्सा उपकरण, रक्षा उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण सहित सभी क्षेत्रों में निवेश के लिए बेहतरीन अवसर हैं।

कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों द्वारा अपने अनुभव भी साझा किए गए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया तथा राजस्थानी फाउंडेशन चैप्टर मेंबरशिप की भी लॉन्चिंग की। इससे पहले कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों पर एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई।

इस अवसर पर उद्योग राज्यमंत्री श्री के के बिश्नोई, श्रम विभाग के शासन सचिव श्री पी। रमेश, राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त श्रीमती मनीषा अरोड़ा, प्रवासी समुदाय से ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच के नेशनल प्रेसिडेंट श्री सुरेश एम जैन, हैदराबाद चैप्टर प्रेसिडेंट श्री पवन बंसल, सीआईआई तेलंगाना के पूर्व चेयरमैन श्री साईडी प्रसाद सहित बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी, उद्यमी मौजूद रहे।

□□□

Indo-Japan Relationship:
Work for New Tech & Skill Development

News Flash
Udyog Times Desk

PM Shri Narendra Modi and PM Japan Shri Shigeru Ishiba attended the India-Japan Economic Forum, organized by the CII & Keidanren [Japan Business Federation] at Tokyo on 29th August.

In his address, PM Modi highlighted the success of the India-Japan Special Strategic & Global Partnership, in particular the bilateral collaboration in the fields of investment, manufacturing and technology. Inviting Japanese companies to further enhance their footprint in India, he noted that the Indian growth story presented exciting opportunities for them. He stated that deepening economic partnership between trusted friends were particularly relevant in the context of the present turbulent global economic scenario.

Shri Modi emphasised that political stability, policy predictability, commitment to reforms and Ease of Doing Business efforts gave a new confidence to investors in the Indian market, which is aptly reflected in the latest credit rating upgrade of India by global agencies.

Underlining the significant potential for collaboration in cutting edge technologies, manufacturing, investments and human resource exchanges between India and Japan, Prime Minister stated that India was contributing around 18% to global growth and was on course to become the third largest economy in the world in a few years. Given the complementarities of the two economies, he highlighted five key areas for greater business collaboration between Japan and India towards Make in India and other initiatives including 1) Manufacturing batteries, robotics, semiconductors, ship-building and nuclear energy; 2) Collaboration in Technology & Innovation, including in AI, Quantum Computing, Space & Biotech; 3) Green Energy Transition; 4) Next-Gen Infrastructure, including mobility, high speed rail and logistics; and 5) Skill development and people-to-people ties.

Prime Minister Ishiba, in his address, noted the interest of Japanese companies in forming partnerships between Indian talent and Japanese technology to build resilient supply chains. He underlined three priorities between India and Japan: strengthening P2P partnerships, fusion of technology, green initiatives and market, and cooperation in critical sectors of high and emerging technologies, in particular semiconductor.

The report of the 12th India Japan Business Leaders' Forum (IJBLF) was presented by the co-chairs of IJBLF to both leaders. Highlighting the burgeoning partnerships between Indian and Japanese Industry, Shri Norihiko Ishiguro, Chairman and CEO of the Japan External Trade Organization (JETRO), announced various B2B MoUs signed between Indian and Japanese companies in a range of sectors such as steel, AI, space, education and skills, clean energy and human resource exchanges.

□□□

लघु उद्योग भारती / विश्वकर्मा जयंती उत्सव

Andaman and Nicobar

Belgavi Karnataka

Bilaspur Chhattisgarh

Chandigarh

Goa

Chhindawada Madhya Pradesh

Delhi National Ho

Deharadoon

लघु उद्योग भारती / विश्वकर्मा जयंती उत्सव

Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan

Jamnagar Gujarat

Jorahat Golaghat Assam

Nagpur Maharashtra

Palakkad, Kerela

South Bengal, Howrah

Telangana

Vishakhapattanam Ap

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं टेक्नोलॉजी की मदद से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर

तकनीक

अनिल पाठक

प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर डायरेक्टर

एग्जीक्यूटिव काउंसिल-IEEE

(इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स)

दिल्ली चैप्टर

anil.pathak@ieee.org

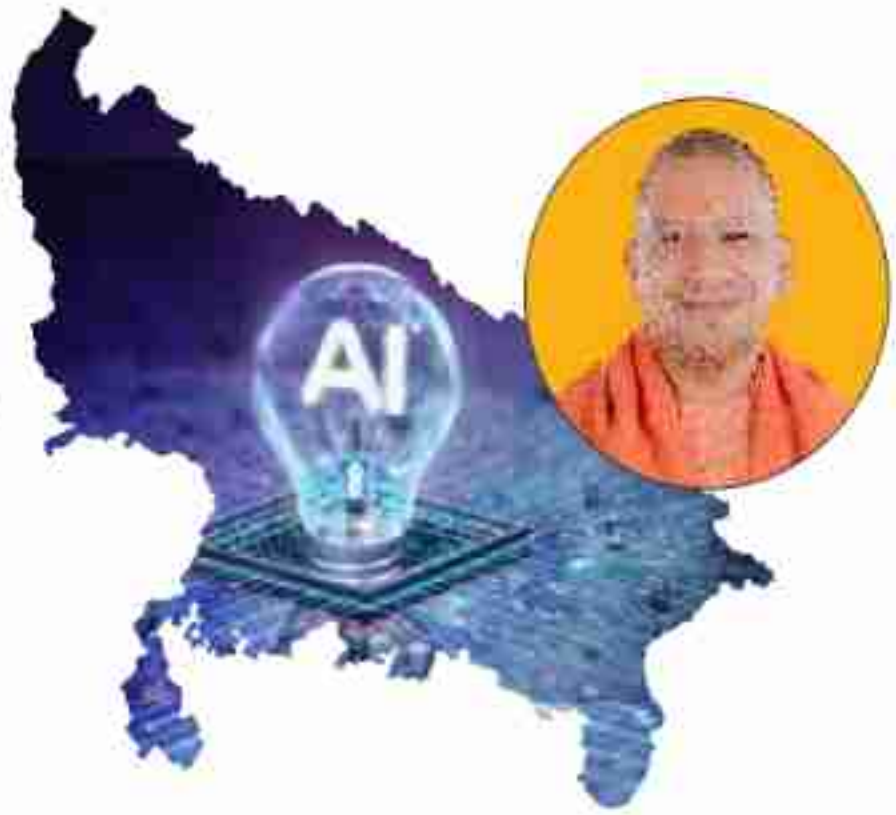

उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उन्नति की राह पर निरंतर अग्रसर है। इस प्रगति की रफ्तार को और गति देने के लिए प्रदेश की सरकार तकनीकी (टेक्नोलॉजी) के क्षेत्र में हो रहे नवाचार (इन्नोवेशन) का भी उपयोग कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनने के सपने को पूरा करने में उत्तर प्रदेश की अपनी एक ख़ास भमिका है। इसी संदर्भ में श्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की GSDP को अगले कुछ वर्षों में 1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को टेक्नोलॉजी की मदद से ही जल्दी पूरा किया जा सकता है। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार कई वर्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग कई विभागों में कर रही है जैसे हाल में ही संपन्न हुआ कुंभ मेला, लॉ एंड ऑर्डर प्रबंधन, पुलिस रिफॉर्म्स आदि। लेकिन अब उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के अवसर को एक समग्र रूप में अपनाने के लिए कार्यरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इस बदलाव के केंद्र में है, जो उत्तर प्रदेश को 'उत्तम प्रदेश' बनाने की दिशा में एक शक्तिशाली इंजन का काम कर रहा है।

सरकार, MSME और शिक्षाविदों के संयुक्त प्रयासों से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न केवल राज्य की आर्थिक तस्वीर बदल रहा है, बल्कि शासन–प्रशासन, कृषि, शिक्षा और नागरिक सेवाओं में भी क्रांति ला रहा है। उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से एक डिजिटल और उन्नत राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत करके विकास को गति देने के लिए कई महत्वाकांक्षी पहल कर रही है।

वैसे तो उत्तर प्रदेश में कई योजनाएं प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने में सहायक हैं लेकिन निम्नलिखित योजनाएं प्रदेश को विशेष रूप से गति प्रदान कर रही हैं ।

- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022
- उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति–2022
- उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति–2020 / 2022
- उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति–2021
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति–2020

अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति–2024 का प्रदार्पण किया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की ज्पमत–2 शहरों में GCC को स्थापित करने के लिए

प्रोत्साहित किया जाएगा। वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) बहुराष्ट्रीय निगमों (MNC) के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उत्पाद विकास (Productivity Enhancement), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा

(Cyber Security) जैसे प्रमुख व्यावसायिक कार्यों के लिए नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर विकास के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दे रही है–

1. कौशल विकास, प्रशिक्षण और जन–भागीदारी
2. कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं टेक्नोलॉजी का प्रयोग
3. MSME सेक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) व अन्य टेक्नोलॉजी से मदद करना

कौशल विकास और प्रशिक्षण और जन-भागीदारी-

उत्तर प्रदेश सरकार टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Tata Technologies Ltd.) के सहयोग से राज्य भर में 75 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को अपग्रेड करने का फैसला पहले ही कर चुकी है। यह पहल उद्योग 4.0 (Industrial 4.0) की आवश्यकताओं के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्रों को वैश्विक औद्योगिक मानकों को पूरा करने के लिए उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण मिले।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को आम जन तक पहुँचाने और एक विशाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) – तैयार कार्यबल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने "AI प्रज्ञा" जैसी पहलें शुरू की हैं। इसका लक्ष्य 10 लाख से अधिक लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में प्रशिक्षित करना है, जिनमें शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, छात्र और अन्य पेशेवर शामिल हैं। राज्य के सभी 75 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, और मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जा रहे हैं जो बाद में दूसरों को प्रशिक्षित करेंगे। अप्रैल–मई 2025 तक की रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने अगले 4–6 महीनों में 10 लाख लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीकों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है, और हर महीने 1.5 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना है। माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft), इंटेल (Intel), एचसीएल (HCL), 1M1B और वाधवानी (Wadhwani) जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों के साथ साझेदारी इस कार्यक्रम की गंभीरता को दर्शाती है। यह कौशल विकास कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लाभ केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित न रहें, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुँचें, जिससे डिजिटल साक्षरता बढ़े और रोजगार के नए अवसर खुलें।

कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं टेक्नोलॉजी का प्रयोग-

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है।

- यूपी–एग्रीस UP AGREES (Uttar Pradesh Agriculture Growth and Rural Enterprise Ecosystem Strengthening) कार्यक्रम, विश्व बैंक के सहयोग से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके कृषि उत्पादकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि पर केंद्रित है। AI–आधारित ड्रोन और सेंसर का उपयोग करके फसल स्वास्थ्य की निगरानी और कीटों का पता लगाने से उपज में सुधार हो रहा है।
- **''उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर** (UPONA)'' जैसी परियोजनाएँ, जो गूगल क्लाउड

(Google Cloud) के साथ साझेदारी में हैं, किसानों को वास्तविक समय में मौसम की जानकारी, मिट्टी के स्वास्थ्य का विश्लेषण, फसल सलाह, ऋण और बाजार से जुड़ाव जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं।

MSME सेक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) व अन्य टेक्नोलॉजी से मदद करना

MSME सेक्टर का उत्तर प्रदेश के विकास में एक महत्पूर्ण योगदान है इस सन्दर्भ में प्रदेश सरकार कई बिंदुओं पर कार्य कर रही है।

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फंड**– उत्तर प्रदेश सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप्स और अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फंड बनाने पर विचार कर रही है । इस फंड का ज्यादा लाभ स्टार्टअप एवं MSME सेक्टर को ही होगा ।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिटी– नवाचार का केंद्र**

आपने लखनऊ के बारे में सुना होगा जो हमेशा औरों को पहले आप, पहले आप कह कर औरों को मौका देता है। जैसे किसी शायर ने कहा है–

तहज़ीब लाजवाब, पहले आप पहले आप !

अंदाज़–ए–गुफ़्तगू यहाँ का है ख़ास !

है लखनऊ जनाब, पहले आप पहले आप।

इसी तरह लखनऊ शहर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिटी का निर्माण कर सब को लखनऊ आकर रोजगार देने का न्योता दे रहा है। लखनऊ में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिटी का विकास उत्तर प्रदेश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्रांति का सबसे महत्त्वाकांक्षी कदम है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिटी का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक समर्पित केंद्र बनाना है, जो अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा, तकनीकी संस्थानों और औद्योगिक निवेश को आकर्षित करेगा। यह शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शैक्षणिक, औद्योगिक और तकनीकी संस्थानों का हब बनेगा, जिससे बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों पर निर्भरता कम होगी। यहाँ अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ, डेटा सेंटर और एक मजबूत तकनीकी बुनियादी ढाँचा विकसित किया जा रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(AI) स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों दोनों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगा। यह पहल न केवल प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करेगी बल्कि एक नवाचार–संचालित अर्थव्यवस्था को भी गति देगी।

उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को केवल एक तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के एक माध्यम के रूप में देख रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करके, उत्तर प्रदेश न केवल तकनीकी रूप से उन्नत होगा, बल्कि MSME क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाएगा और देश के तकनीकी मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान हासिल करेगा।

अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हालाँकि चर्चा के लिए कई

पवेलियन थे, लेकिन स्टार्टअप पवेलियन (Start in UP) प्रमुख आकर्षण का केंद्र था । 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स ने AI,ML,GenAI, IOT, EV Agritech और Sustainability में समाधान प्रदर्शित किए। लाइव डेमो, पिच सेशन और पैनल वार्ता ने निवेशकों, सलाहकारों और VCs को आकर्षित किया।

AI पवेलियन में उभरते AI applications और LLM (Large language models) आधारित chatbots का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनों में SIA (स्किल इंडिया असिस्टेंट), स्मार्ट गवर्नेंस के लिए AI और predictive analytics समाधान शामिल थे। मुख्य ध्यान "जनहित के लिए एआई" और "मेक–इन–यूपी के लिए एआई" पर केंद्रित किया गया था।

अंततः इस बात में दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश 'उत्तम प्रदेश' बनने की राह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाकर एक नया अध्याय लिख रहा है।

यह एक ऐसा भविष्य है जहाँ तकनीक आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाएगी, शासन को अधिक प्रभावी बनाएगी, और राज्य को एक वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हब के रूप में स्थापित करेगी।

□□□

वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के लिए उद्योग उड़ान-2025 आयोजित

वाइब्रेंट गुजरात निवेश समिट को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर उद्यमियों को जागरुक करने के क्रम में लघु उद्योग भारती एवं जिला उद्योग केंद्र, साबरकांठा ने संयुक्त रूप से विशेष चर्चा सत्र हिम्मतनगर में 10 सितम्बर को आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पद्मश्री सवजीभाई ढोलकिया (संस्थापक, हरिकृष्ण एक्सपोर्ट प्रा. लि., सूरत) ने कहा कि व्यवसाय की प्रगति उद्यमी के हाथों में ही है। कर्मचारियों व उनके परिवारों को सुखी रखें, सहयोग दें, यही सफलता का मार्ग है। उन्होंने मानवता व राष्ट्र निर्माण हेतु योगदान देने का आह्वान किया और जल–संचय हेतु झील निर्माण के उदाहरण साझा किए।

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा ने छोटे उद्यमियों को संगठन से जुड़ने व राष्ट्र निर्माण में योगदान का आह्वान किया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलदेव भाई प्रजापति ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। श्री श्यामसुंदर सलूजा ने जिले की औद्योगिक स्थिति व आवश्यक सुविधाओं पर प्रकाश डाला। प्रदेश अध्यक्ष श्री ईश्वरभाई पटेल, महासचिव श्री हंसराजभाई गजेरा, अध्यक्ष श्री अरविंद भाई पटेल, महासचिव श्री अशोक भाई पटेल, औद्योगिक महासंघ अध्यक्ष श्री कांतिभाई शाह, नगर पालिका अध्यक्ष श्री विमल भाई उपाध्याय ने भी संबोधित किया।

द्वितीय सत्र में सांसद श्रीमती शोभना बेन बरैया व विधायक श्री वी.डी. झाला ने सरकार की नीतियों हेतु आभार व्यक्त कर 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य हेतु उद्यमियों को रोजगार सृजन व उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जिले में दो नए GIDC स्वीकृत हो चुके हैं। जिला कलेक्टर श्री ललित नारायण सिंह सदूण ने आश्वासन दिया कि प्रशासन औद्योगिक समस्याओं में हर संभव सहयोग देगा। डीडीओ श्री हर्षदभाई वोरा ने भी उद्यमियों को संबोधित किया। जिला उद्योग केंद्र प्रबंधक श्री मिहिर भाई मकवाना ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन श्री योगेश भाई रावल व डॉ. किरीटभाई पटेल ने किया। जिला अध्यक्ष श्री श्रीपाल शाह ने संयोजन एवं जिला मंत्री श्री विपुल भाई पटेल ने आभार व्यक्त किया।

□□□

समालखा सम्मेलन में लघु उद्यमियों के कुंभ का दिग्दर्शन

लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय कार्यसमिति में हुआ उद्योग हितैषी चिंतन

विशेष रिपोर्ट

रमन सलूजा

प्रदेश कोषाध्यक्ष

लघु उद्योग भारती, हरियाणा

ramansaluja@oewin.com

हरियाणा के समालखा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यसमिति के तीसरे और अंतिम दिवस 15 सितम्बर को उद्यमी सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मान्य सह सरकार्यवाह श्री (डॉ.) कृष्ण गोपाल जी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचंद्र जी, उत्तर क्षेत्रीय संघचालक श्री पवन जिंदल, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा भाजपा प्रभारी श्री सतीश पूनिया, उद्योग मंत्री श्री नरबीर सिंह, एलयूबी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा और राष्ट्रीय महासचिव श्री ओमप्रकाश गुप्ता सहित देशभर से संगठन के समर्पित पदाधिकारीगण एवं 15 सौ से अधिक सदस्य उद्यमियों की सजीव उपस्थिति में लघु उद्योगों के लिए वैचारिक मंथन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारम्भ मां भारती और भगवान विश्वकर्मा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम का संचालन कर रहे **एलयूबी हरियाणा प्रदेश के**

अध्यक्ष श्री शुभ आदेश मित्तल ने अतिथियों और भारत के सभी राज्यों से आए एलयूबी प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

श्री मित्तल ने बताया कि गत ग्यारह वर्षों से हरियाणा प्रदेश में उद्यमियों के हितों के लिए शासन की ओर से संवेदनशीलता दिखाई गई है। निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदेश की सरकार ने कुछ विशेष कदम उठाये हैं। जिनसे निश्चित रूप से लघु उद्यमियों को राहत मिली है।

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा ने अपने औपचारिक स्वागत भाषण में कहा कि हरियाणा सरकार उद्यमियों के उद्योग संचालन के लिए सुगम व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है जो निश्चित रूप से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कारगर होगी।

श्री ओझा ने बताया कि बीते तीन दशकों की यात्रा में लघु उद्योग भारती ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों के संरक्षण, संवर्धन और कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किये हैं। संगठन ने एमएसएमई सेक्टर के लिए नीति–निर्धारण में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। उन्होंने बताया कि देशभर में संगठन ने

596 जिलों के 1254 इंडस्ट्रीज एरिया में 1056 इकाइयों और 61,924 सदस्य संख्या के साथ विशाल नेटवर्क खड़ा कर दिया है।

कार्यक्रम के **मुख्य अतिथि और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह** ने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों की सफलता में लघु उद्योगों की भूमिका सर्वोपरि है। उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा भारत में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने में देशभर में सातवें स्थान पर आ चुका है।

उन्होंने जानकारी दी कि नए उद्योग और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में इन्क्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र स्टार्टअप को शुरुआती चरण में आवश्यक संसाधन, तकनीकी सहायता, परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

श्री नायब सिंह ने बताया कि हरियाणा भारत में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने में देश भर में सातवें स्थान पर आ चुका है। प्रदेश में दस नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (IMT) विकसित करने की योजना बनायी गई है, जिनमें 3 नए IMT राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकसित करने के लिए भूमि प्राप्त की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक विशेष नीति लागू की गई है। रोहतक में EV पार्क स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि समालखा में लघु उद्योग भारती के तीन दिवसीय औद्योगिक चिंतन से लघु उद्योगों के विकास को नई दिशा मिल सकेगी। Make in India और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों की सफलता में लघु उद्योगों की भूमिका सर्वोपरि है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हरियाणा में एमएसएमई का समर्थन कर रही है और एलयूबी द्वारा ध्यान में लाए गए कई मुद्दों को एमएसएमई के हित में निपटाया गया है।

कार्यक्रम के **विशिष्ट अतिथि और केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर** ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार उद्योग हितैषी नीतियों से भारत में नई औद्योगिक संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। भारत सरकार एमएसएमई की बेहतरी के लिए कई नीतियाँ बना रही है, क्योंकि ये समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए रोज़गार सृजन और कौशल विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

श्री खट्टर ने कहा कि कई वर्षों के बाद, देश जीएसटी को कुछ ही स्लैब में सीमित कर पाया है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बड़ी कंपनियों में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को छोटे उद्योगों में भी सशक्त भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के स्वरूप को भी परिवर्तित करने का समय है और यदि युवाओं को छोटे–छोटे स्किल्स सिखाकर उनका कौशल विकास कर दिया जाए, तो वे न केवल रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने गाँव और शहर में स्वयं का काम आरंभ कर आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मान्य सह सरकार्यवाह और लघु उद्योग भारती के पालक अधिकारी श्री कृष्ण गोपाल जी ने कुटीर और लघु उद्योगों को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल इन उद्योगों से रोजगार के विपुल अवसर सृजित किये जा सकते हैं जबकि बड़े उद्यम अधिक तकनीक अपनाकर भी बहुत कम रोजगार पैदा कर पाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधिक प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन और पूंजीवाद से बेरोजगारी ही बढ़ती है। जैसे–जैसे पूंजी कुछ हाथों में सिमटती जाती है वैसे–वैसे कम आय वाले लोग मरते जाते हैं।

कार्यक्रम में एचएसआईआईडीसी के इंडस्ट्री कॉर्डिनेटर श्री सुनील शर्मा ने हरियाणा के उभरते औद्योगिक परिदृश्य पर 'इन्वेस्ट इन हरियाणा इनवेस्ट इन फ्यूचर' शीर्षक से प्रभावी डिजिटल प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि 19 यूनिकॉर्न हरियाणा की नई पहचान बना रहे हैं। श्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश मेडिकल टूरिज्म का हब बनने जा रहा है।

राष्ट्रीय कार्यसमिति और अधिवेशन में भाग लेने आये लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव श्री राकेश गर्ग का मानना है कि ऐसे कार्यक्रम में सहभागिता से नई अंतर्दृष्टि मिलती है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अरविंद धूमल कहते हैं कि देशभर की औद्योगिक समस्याओं और उनके समाधान के लिए संगठन में एक समान सोच विकसित होता है। इसी तरह राष्ट्रीय सचिव श्री नरेश पारीक ने भी ऐसे अवसरों को नयी ऊर्जा का संचार करने वाला बताया। तो वहीं मास कम्युनिकेशन आयाम के अध्यक्ष श्री अतीत अग्रवाल उद्योगों के लिए नयी तकनीक और नवाचारों को जानने का बेहतर माध्यम बताते हैं।

कार्यक्रम स्थल पर उद्योग प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें जेम और लघु उद्योग भारती की स्टॉल पर उद्यमियों को परामर्श देने के साथ जेम पोर्टल और लीप पोर्टल पर औद्योगिक इकाइयों की लिस्टिंग की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पत्रिका उद्योग टाइम्स के विशेषांक 'उद्योग उत्थान' का अतिथियों ने मंच पर विमोचन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव श्रीमती अंजू बजाज और को–एडिटर डॉ. संजय मिश्रा भी उपस्थित रहे।

महासचिव सीए श्री मनोज रुंगटा ने आभार व्यक्त किया। सम्मेलन में लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वजुभाई वघासिया, श्री बलदेवभाई प्रजापति, श्री ओमप्रकाश मित्तल और श्री जितेन्द्र गुप्त सहित विविध औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं उद्यमीगण उपस्थित रहे।

टीम समालखा सक्रिय सदस्य

समालखा में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति और उद्यमी सम्मेलन को प्रदेश अध्यक्ष श्री शुभ आदेश मित्तल के नेतृत्व में एक सुदृढ़ टीम ने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री अरुण बजाज, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री रमन सलूजा, पानीपत जिला अध्यक्ष श्री कपिल गुप्ता, प्रदेश महामंत्री श्री मनोज रुंगटा, प्रदेश मंत्री श्री भूपिंदर शर्मा, अम्बाला अध्यक्ष श्री विनोद बंसल एवं महामंत्री श्री सुभाष चंद्र, फरीदाबाद अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता, करनाल अध्यक्ष श्री अभिषेक गुप्ता एवं सोनीपत से श्री संदीप गोयल शामिल हैं। साथ ही दिल्ली एवं केंद्रीय कार्यालय की टीम ने भी इस सफल आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती अंजू बजाज, राष्ट्रीय मंत्री श्री नरेश पारीक, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री दिवान चंद गुप्ता, महामंत्री श्रीमती आरती सहगल।

अधिवेशन के दौरान जो मार्गदर्शन अखिल भारतीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा जी एवम् राष्ट्रीय महासचिव श्री ओमप्रकाश गुप्ता जी का हर स्तर पर प्राप्त हुआ, वह अविस्मरणीय रहेगा।

समालखा उद्यमी सम्मेलन के मुख्य प्रायोजक हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन (HSIIDC) का विशेष सहयोग रहा। □□□

Glimpses @ LUB's Samalkha (Haryana) Adhiveshan

CA Manoj Rungta, Shri Arun Bajaj, Shri Raman Saluja & Shri Kapil Gupta felicitates CM Shri Nayab Singh

LUB's Team Samalkha Honoring Inspiring Leader & Haryana BJP In-Charge Dr. Satish Poonia

Team Samalkha Welcomes National President Shri Ghanshyam Ojha

Women Participation ensures the Real Women Empowerment

RSS Seh Sarkaryawah Shri Krishna Gopal ji, Union Minister Shri Manohar Lal Khattar, CM Haryana Shri Nayab Singh, Haryana BJP In-Charge Dr. Satish Poonia, Industry Minister Shri Narbir Singh, Kshetriya Sangh Chalak Shri Pawan Jindal and LUB's Officials released Special Issue Udyog Utthan

किसी भी ढंग से पैसा कमाना हमारा आदर्श नहीं, लेकिन नैतिक मूल्य जरूरी

मार्गदर्शन
प्रकाशचंद्र
राष्ट्रीय संगठन महामंत्री
लघु उद्योग भारती

(समालखा में राष्ट्रीय कार्यसमिति को संबोधन का संपादित अंश)

लघु उद्योग भारती ने अपनी स्थापना के बाद से लघु उद्योगों की समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए निरंतर प्रयास किये हैं। शासन में अनुकूल या प्रतिकूल कैसी भी सरकारें रही हों, लेकिन कई कठिन विषयों का समाधान भी संभव हुआ है। आने वाले वर्षों में इस प्रकार योजना बनाकर आगे बढ़ें जो सर्वव्यापी, स्वपक्षीय हो। हमारा दायित्व अधिक है। समाज लघु उद्योग भारती से अपेक्षा करता है। हम प्रयत्न करें, प्रयास करें। सब प्रयास सफल नहीं होते, पर प्रयास निरंतर करते रहें।

सौ वर्ष पुरानी हमारी विचार यात्रा है। स्वाधीनता को सत्तर–अस्सी वर्ष हो गए। अब भविष्य के लिए नैतिकता का प्रतिमान क्या है? पर्यावरण के संबंध में क्या दृष्टिकोण है? जिस प्रकार बार–बार खाद डालने से मिट्टी भी विषैली हो गई है, इससे समाज और विश्व भविष्य को लेकर चिंतित है। ऐसे प्रश्नों के समाधान के संदर्भ में वह हमें देखते हैं और हमसे समाधान के प्रयास की अपेक्षा भी है। हम समाज का नेतृत्व करने वाले और पीड़ा को समझने वाले लोग हैं। हमारा दायित्व अधिक है। किसी भी ढंग से पैसा कमाना हमारा आदर्श नहीं है। हमारे समाज की विशेषता है कि अच्छे संकल्प को लेकर जब कोई चलता है, तो प्रारंभिक उपेक्षा, उलाहना के पश्चात समाज साथ चल पड़ता है। सब ऐसा मानते हैं कि देश, समाज–हित के विषयों का समाधान हम कर सकते हैं। प्रशासन के समक्ष पूरी तैयारी से विषय रखें।

4–5 हज़ार वर्ष का प्रमाण है कि आर्थिक, व्यापारिक दृष्टि से हम शीर्ष पर रहे। अन्य शक्तियां सौ, 3 सौ वर्षों में लड़खड़ा गईं। केवल समृद्धि ही नहीं, अपितु संस्कारों के कारण हज़ारों वर्षों तक हम टिके रहे। नैतिक मूल्य टिकाए रखते हैं। मुहम्मद–बिन–क़ासिम, महमूद–गजनवी, मुहम्मद गोरी, खिलजी, तैमूर, मुगल सभी आए और हमको लूटा, लेकिन हमारी समृद्धि को खाली नहीं कर सके। हम कंगाल तब हुए, जब अंग्रेज़ ने हमारे उद्योगों को नष्ट करने का काम किया और हमारी मानसिकता को, हमारे गौरवशाली अतीत को विस्मृत किया। स्वाधीनता के पश्चात भी कुछ कालखंड तक यही रहा। किन्तु अब भविष्य के लिए हमारे लिए अच्छी कल्पना है। समृद्धि भी आए, लेकिन संस्कार भी आएँ।

पंच परिवर्तन से हम अब 2025 से आगे बढ़ेंगे। यह हमारे रक्त में है कि बढ़ेंगे और नैतिकता से समृद्धि को टिका पाएंगे। अच्छी मानसिकता के साथ जीवन के लक्ष्य निर्धारित करें। समृद्धि को लक्ष्य मानकर, अन्य बढ़कर डूब गए। केवल आर्थिक मानव नहीं, सामाजिक मानव भी। अध्यात्म से जीवन मूल्य बनाए रखें, तभी बढ़ेंगे और टिकेंगे। "By hook or by crook" के रास्ते पर चलने वाले अधिक देर तक टिके नहीं रहते। व्यक्ति से लेकर परिवार तक नैतिकता के अधिष्ठान स्थापित करें। कमाओ भी लेकिन दान भी करो। समाज का परिवेश बहुत अच्छा नहीं, पर बहुत बुरा भी नहीं। कोरोना में स्वयं भी सँभले, अन्यों को भी संभाला। यही हमारी सामान्यतः परंपरा है। एक उद्यमी के नाते भी अच्छी रीति / प्रथा (good practice) के साथ आगे बढ़ें। हर कोई हर वस्तु नहीं उगा सकता, मिलकर बढ़ें। हमने LEAP के प्लेटफार्म पर अपलोडिंग शुरू कर दी है, उत्पाद समूहों, क्लस्टर्स, आईटीआई के बारे में प्रगति जारी है।

सरकार की योजनाएं कुछ ही व्यक्तिगत के लाभ के लिए हैं, अन्य सामूहिक रूप से संगठन का उपयोग कर उद्यमिता को कैसे प्रोत्साहित करें, उनका लाभ ले सकते हैं। प्रौद्योगिकी उन्नयन को लेकर जेम (GeM) आदि जितने भी विषय हैं, संस्थानों से मिलकर एमओयू कर ऐसे अनेक प्रयत्न मिलकर गति बढ़ा सकते हैं।

लघु उद्योग भारती के मंच का समस्या समाधान के साथ लाभ भी कैसे लें, निरंतर चिंतन करें। साथ चलने वाले, जुड़ने वाले उद्यमियों को राहत देने के लिए प्रयास करें। सरकार से लेना, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना इसका अध्ययन करते रहें। उत्पाद समूह के लिए प्रदेशों से उद्यमियों को चिन्हित कर केंद्र को भेजें। सरकारी नीतियों का आवश्यकतानुसार दोहन कर हर उद्यमी को कुछ न कुछ राहत मिलेगी। □□□

LUB's All India Working Committee & Executive Meeting

13-14 Sept. 2025 @ Village Patti Kalyana, Samalkha Block, Haryana

The First Session began with lamp lighting on 13th Sept. Following the Bhayandar, Mumbai meeting, All India office bearers presented their travel (Pravas), information scheduled meetings and reports. Also discussed on special programs initiated during RSS Centenary Year.

In **Second Session**, the agenda for the AIWC & Executive Meeting (Sept. 14) and the Udyami Sammelan (Sept. 15) was finalized. The locations for the proposed AIWC Meetings in December-2025 & January-2026 were decided. **All India Organizing Secretary Shri Prakash Chandra Ji** share valuable inputs and guidance.

On Sept. 14, after the Sangthan Mantra, **All India President Shri Ghanshyam Ojha** expressed happiness on the completion of 100 years of RSS, as even large organizations disappear after a few years. He said that we will always strive to fulfil the purpose for which Laghu Udyog Bharati was established and will always work in the interest of MSMEs under all circumstances.

Swavalambhi Bharat Abhiyan/Self-Employment Work Review: Shri Jitendra Gupta informed about the meaningful efforts being made for SBA and the work being done by different states. Explaining the role of self-employment, he said that it can play the role of Job Provider instead of Job Seeker.

Gram Shilpi: Shri Yogendra Sharma said that the government has created the Vishwakarma Yojana for thousands of Artisans. LUB should play a supporting role to provide them an appropriate marketing opportunity through Trade Fairs, Exhibitions, and Portals like LEAP.

IMS: Shri HVS Krishna gave a detailed presentation on the 7th IMS Exhibition to be held in Bangalore on November 6-8, 2025 and invited all members to participate.

Women's Work & Swayamsiddha: Smt. Anju Bajaj and Smt. Uma Sharma presented reports from all states. Exhibitions are being successfully organized in many states under Swayamsiddha.

India Industrial Fair (IIF): The 12th edition of IIF is being held in Bhiwadi from Sept.19-21, 2025 with 350 stalls. Its 13th edition will be held in Guwahati from October 30 to November 2, 2025.

Open Forum Discussion & Suggestions: Members welcomed the Prime Minister's announcement of reducing the GST rates. Members made suggestions to expand and accelerate the work of LUB, which are being implemented.

All India General Secretary Shri Om Prakash Gupta thanked all the members and said that in the last 31 years, the organization has continuously achieved new dimensions. Laghu Udyog Bharti's contribution towards the upliftment of the industry, service to society, and self-reliant India has been possible due to dedication and cooperation of the members.

□□□

Insightful Presentations & Proceedings during All India Working Committee @ Samalkha

Dates: 13-15 Sept. 2025
Venue: Sewa Sadhana & Gram Vikas Kendra
Run by Shri Madhav Jan Sewa Nyas
Village- Patti Kalyana, Samalkha Block, District- Panipat, Haryana

Presentation on GeM

Shri Anurag Awasthi, Chief Manager GeM informed that GoI has purchased 5.60 Lakh crores through GeM in the last year. Now it has set a target of Rs.10 Lakh crores for this year.

LUB's National GS Shri OP Gupta suggested that there should be a GeM Mitra plan for each unit of LUB in India.

Presentation on Cluster Development Scheme

by Shri Sanjeev Chawla, Additional Development Commissioner, Karnal MSME- (DFO) Karnal

The North-Eastern Italy; people used to discuss, how to negotiate with govt., how to make purchases cheaper. A Harward Prof. Michael E. Porter in his book "The Competitive Advantage of Nations" writes that, National prosperity is created, not inherited (which is a report on his 4-year, 10 Nation study of the patterns of competitive success in leading trading countries). It does not grow out of a country's natural endowments, its labour pool, its interest rates or its currency's value, as classical economics insists. A nation's competitiveness depends on the capacity of its industry to innovate & upgrade".

Shri Sanjeev Chawla insisted that when we work together, many solutions are there. Groups of industry develop together through clusters. LUB can play a role in bulk buying, which is cheap.

- Britishers broke the backbone of our industry. In 1954, the Indian Govt. established the Small-Scale Industries (SSI) Sector, by creating the Small-Scale Industries Board. In 1999, the first MSME Ministry was created with Smt. Vasundhara Raje Scindia as its Minister. In 2006 MSME Act came into force.

About technology transfer he said that, till the first batch of product is not sold in the market, it should not be deemed as Technology Transfer.

- MSME definition in other countries is sector wise, whereas in India it is based on Turnover (excluding Exports, if investment is less than Rs.125 crores). He said that the central govt. plays a promotional role in policy making.
- About the packaging problem of artisans, he suggested going for available packaging to avoid costs, instead of new packaging.
- He said that the GST number is not mandatory for the MSMEs registration process for businesses or entities that do not require GST registration. However, enterprises or businesses whose annual turnover is above 40 Lakhs are taxable entities, so they need to have a GST registration.
- He said that the central govt. facilitates SME exchanges through the stock exchanges. These exchanges provide SMEs with easier access to funding through IPOs.
- He talked about the SRI (Self Reliant India) Fund is an Aatmnirbhar Bharat initiative of the Indian govt., launched in 2020 to provide Rs.50 thousand crores in equity support to viable MSMEs with

growth potential.

Objective of the Micro & Small Enterprises Cluster Development Program (MSE-CDP Scheme)

I). Improve Technology and Skills:

To support MSEs in adopting new technologies, enhancing quality standards, and building the skills necessary for growth.

ii). Enhance Market Access:

To help MSEs gain better access to markets by addressing their common challenges and fostering collective marketing efforts.

iii). Promote Collaboration:

To build the capacity of MSEs for collective action through the formation of self-help groups, consortia, and the upgradation of industry associations.

iv). Create/ Upgrade Infrastructure:

To support the establishment and improvement of physical infrastructure in existing or new industrial areas and clusters.

v). Establish Common Facilities:

To set up Common Facility Centers (CFCs) that provide services such as testing, training, raw material depots, effluent treatment, and other complementary production processes.

vi). Encourage Green Manufacturing:

To promote sustainable and green manufacturing technologies, enabling MSEs to adopt environmentally friendly production processes and products.

vii). Holistic Development:

To facilitate the comprehensive growth of MSEs by addressing their common needs and challenges through a cluster-based approach.

Characteristics of a Cluster-

A cluster is a geographical or value chain-based grouping of similar or complementary businesses sharing common infrastructure, resources, and challenges to foster cooperation and competitiveness. Key characteristics include shared production processes, technology, market needs, and a sense of collective identity. A common facility centre (CFC) is a shared infrastructure within a cluster providing specialized services or equipment to members, such as machinery, energy, or quality control facilities, to reduce costs and address common challenges collectively.

EPR (Extended Producers Responsibility)-

EPR stands for Extended Producer Responsibility, a policy approach where producers, importers, and brand owners are held responsible for managing the environmental impact of their products throughout their entire lifecycle, especially at the post-consumer stage. This "polluter pays" policy [which is built on the principle that those who create the waste should be responsible for managing it] shifts the burden of waste management from municipalities and taxpayers to the producers, encouraging them to design more sustainable products and use eco-friendly materials to reduce waste. EPR schemes involve setting targets for collection, recycling, and reuse, and often require producers to register on a centralized portal to ensure compliance.

MSE Cluster Development Programs, Funding Pattern of Projects-

The MSME Cluster Development Program's funding patterns involve contributions from the Government of India, State Governments, and the Special Purpose Vehicle (SPV) for projects like Common Facility Centers (CFCs) and infrastructure development. The Government of India typically contributes a higher percentage, with a base rate of 60-70% for CFCs and 50-60% for infrastructure, which can increase up to 90% for clusters in North-Eastern and Hill States or those with a majority of micro, women-owned, or SC/ST units. In Tamil Nadu more than 19 Clusters exist. This scheme is officer specific. If an officer takes interest, then it becomes successful. The CFC has to do job-work for cluster members. It cannot do sale/ purchase & cannot participate in Tenders.

Carbon Credits for MSMEs

The Carbon credits present a new income stream and cost-saving opportunity for MSMEs by enabling them to sell surplus emissions reductions to other entities within India's Carbon Credit Trading Scheme (CCTS). MSMEs can also be supported through cluster-based initiatives to aggregate credits, allowing them to benefit from clean energy initiatives and contribute to national climate goals. CBG plant for jaggery waste in Chhattisgarh, poultry waste etc.

A Special Purpose Vehicle (SPV) can pay the share that would typically be the state governments, but this

arrangement is subject to the specific terms and conditions outlined in the project's financing, ownership structure, and governing legal framework. For instance, in some projects, grants provided by the central government can be used as the state or local urban body's share of equity in the SPV, though this is dependent on meeting the conditions set by the governing ministry.

CCEA Guidelines for a Cluster SPVCCCCE-

The guidelines for a cluster SPV are laid down by CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs) which involves its formation as a registered legal entity, with the SPV's role and functions clearly defined, and the procurement and registration of land in the SPV's name. The project requires an appraised Detailed Project Report (DPR) outlining its benefits for MSMEs, and a dedicated project account in a Scheduled-A bank. The Ministry of MSME (now MSME) promotes these guidelines for cluster development schemes.

Key Requirements for the SPV:

Formation of SPV: A legal entity, such as a company registered under the Companies Act or an industry organization, must be formed to implement the cluster development project.

Defined Role & Functions: The SPV's responsibilities and operational functions within the project must be clearly specified.

Land Procurement: Land for the cluster project must be procured and registered in the name of the SPV.

Detailed Project Report (DPR): The SPV is responsible for preparing an appraised DPR that demonstrates how the proposed Common Facility Center (CFC) or infrastructure will improve the competitiveness of the MSMEs in the cluster.

Project Account: A project-specific account must be opened in a Scheduled A bank.

Shareholding Details: The SPV must provide details of its shareholding structure.

Project Alignment: The DPR should align with the common aspirations of the cluster's enterprises, supported by a credible market study or survey.

Government-Approved Schemes:

The Micro, Small, and Medium Enterprises Cluster Development Program (MSME-CDP) and the Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) are government schemes that promote cluster development through SPVs.

Project Approval Process:

Technical Committee: Projects recommended by a Technical Committee (TEAC) are then forwarded for approval.

National Level Steering Committee: A National Level Steering Committee (NLSC) (or similar body) reviews the projects based on the fulfilment of the above conditions before granting approval.

Presentation on ITIs

by Dr. Sachin B. Sabnis
LUB's State President,
Karnataka,

There are over 15,000 Industrial Training Institutes (ITIs) in India, with the total number of functioning ITIs around 15,034, according to a Public Information Bureau (PIB) report from August 2024. These institutes provide technical and vocational training in various trades and are crucial for developing a skilled workforce in the country.

Key Details:

Total Number: Approximately 15,034 ITIs are currently functioning in India.

Government: Out of these, about 3,298 are Government it is.

Private: The remaining 11,736 are private institutions.

Governing Body: The Directorate General of Training (DGT) under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) implements the Craftsmen Training Scheme through these ITIs across the country.

Role: ITIs play a vital role in providing vocational training and shaping a skilled workforce for various industries, particularly in the manufacturing & services sectors.

- **States with Majority of ITIs in India**

There are 5 states with the most ITIs in India, namely- Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, and Tamil Nadu. Uttar Pradesh has the highest number.

Weaknesses of ITI Ecosystem-

The weaknesses in India's Industrial Training Institute (ITI) ecosystem include poor infrastructure and facilities, outdated and inadequate curricula, a lack of

qualified and updated faculty, poor industry linkage leading to skill mismatch with job market demands, and significant underutilization of capacity with low placement rates. There is also a general lack of focus on important non-technical and soft skills necessary for modern workplaces and a fragmented approach to funding and oversight for skill development programs.

National Scheme for ITI Upgradation (for Skill, Quality & Industry demand)

The "1000 ITI upgradation program" refers to India's newly approved National Scheme for ITI Upgradation, which aims to upgrade 1,000 government ITIs over five years with an outlay of ₹60,000 crore (GoI - 70% i.e Rs. 42,000 Cr., State Govt. - 20% Rs.12,000 Cr. & Industry - 10% Rs. 6,000 Cr.). Announced under the Union Budget 2024-25, the scheme will use a hub-and-spoke model, equipping 200 ITIs as hubs and 800 as spokes with modern infrastructure and industry-aligned courses. The initiative focuses on aligning vocational training with global standards, improving infrastructure, introducing new trades, and enhancing trainer skills to boost student employability and the overall skilling ecosystem.

Key Aspects of the Scheme:

Hub & Spoke Model: 1,000 Government ITIs will be upgraded, with 200 acting as "hub" institutions and 800 as "spoke" institutions, forming clusters of 1 hub with 4 spokes.

Industry Partnership: The program emphasizes strong collaboration with industries to ensure the upgraded ITIs offer courses relevant to real-world needs.

Infrastructure and Technology: The scheme includes funding for state-of-the-art machinery, equipment, and infrastructure to equip the ITIs for advanced training.

New-Age Trades: Focus will be placed on introducing new courses and trades to meet evolving industry demands.

Trainer Capacity Building: A crucial component is providing training to 50,000 trainers through pre-service and in-service programs to enhance their skills and teaching practices.

National Centers of Excellence: In addition to ITI upgrades, the scheme will also establish five National Centres of Excellence for Skilling and upgrade five National Skill Training Institutes (NSTIs).

Implementation: The scheme is a state-led initiative, and States/UTs are required to submit proposals based on their readiness and industry interest.

Role of LUB in Implementation

The LUB members should identify the ITI & participate in industry management committees & act as bridge between ITI & industry, create apprenticeships, training etc., prose improvements how to cater local skill needs & reenergise ITIs as industry driven institutes. For this Dr. Sabnis cited the following examples:

i). Udyog PPP Model in Karnataka; &

ii). Belagavi ITI as a hub with spokes

F. Accounts & B/S

Presentation on LEAP

LUB' Mass Communication Aayam Core Team Member & IT Consultant Shri Abhishek Tiwari shared an important presentation on LEAP Portal entitled- LEAP -Empowering MSMEs for a Digital-First Future. He told that Laghu Udyog Bharati has introduced LEAP (LUB E-Mart Advanced Platform) to build a unified digital marketplace for MSMEs across India. LEAP connects entrepreneurs directly with buyers, opens new market opportunities, and provides digital tools for visibility and growth. With more than 47,000 MSME members already onboarded and over 1,200 products listed, LEAP is not just a platform-it is a movement towards self-reliance, collaboration, and sustainable business growth. As MSMEs lead, engage, accelerate, and prosper together, LEAP stands as a catalyst for transforming India's small industries into global champions.

All India Treasurer & Joint Treasurer Shri Janak Bhatia & Shri (CA) Mahesh Gupta presented the accounts & balance sheet.

i). GST Liability & input Availment;
ii). Inter office reconciliation;
iii). Accounting & Financial Records;
iv). Cash Transactions;
v). Online Fee Collection;
vi). Registration with Revenue Authorities;
vii). Copy of resolution till date;
viii). Copy of Bank statements reconciliation;
ix). Copy of FDRs, interest, certificate received;
x). Changes in Accounting software (Tally);
xi). Proposed Changes (Under discussion).

Proceedings of AGM & Closing Session

I). Last year's AGM minutes were presented & approved;
ii). Balance sheet was presented & also got approved;
iii). Auditors for the next term were appointed;
iv). LUB Haryana & Delhi teams were applauded for the hospitality & arranging this AGM through thanksgiving by all the AIWC, AIEC members & the more than 1500 delegates present there representing all states & UTs of India;
v). All India President Shri Ghanshyam Ojha greeted all the delegates, thanked LUB for providing him an opportunity to lead this prestigious organisation at all India level, expressed satisfaction about his two years term as All India President & gave best wishes to the to be constituted new team;
vi). All India Gen. Secretary Shri OP Gupta presented the progress report of LUB & thanked all for extending full cooperation;
vii). All India Past President Shri Jitender Gupta was requested to regulate the proceedings for the formation of new AIWC for the term 2025-27. He then invited proposals for the post of All India President & Gen. Secretary. At this past All India President Shri OP Mittal proposed the name of **Shri Madhusudan Dadu** for the post of All India President, which was seconded by two more office-bearers & then the name of **Shri OP Gupta** was proposed for the post of All India Gen. Secretary which too was seconded by two more office-bearers & both nominations were accepted & approved by all the delegates present.

After this, the **All India Immediate Past President Shri Ghanshyam Ojha** announced a 54 member new working committee for the term 2025-27, which constituted 7 Vice Presidents, 4 Joint Gen. Secretaries, 2 Joint Treasurers, 5 Secretaries, 5 Past All India Presidents, 23 Executive Members & 2 Special Invitees, in addition to All India Org. Sec., immediate past All India Presidents, New President, Gen. Secretary & Treasurer.

❑❑❑

एलयूबी आइडियाथोन-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न

कौशल केंद्र में 5 हजार युवा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में होंगे स्किल्ड

लघु उद्योग भारती के सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र, जयपुर में आइडियाथोन–2025 का पुरस्कार वितरण समारोह 11 सितंबर को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के रेल और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमेरिका की सिलिकॉन वैली में स्थित ल–बवउइपदंजवत की तर्ज पर राजस्थान में भी इनक्यूबेशन, मेंटरशिप और फंडिंग के लिए नया प्लेटफॉर्म तैयार करने की जरूरत है और इसके लिए लघु उद्योग भारती के साथ भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर काम करें।

श्री वैष्णव ने कहा कि लघु उद्योग भारती के जयपुर में बने आधुनिक कौशल केंद्र में भारत सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 5 हजार युवाओं को स्किल्ड किया जायेगा। इसके साथ ही उनके बेहतर प्लेसमेंट के लिए भी प्रयास किये जायेंगे।

श्री वैष्णव ने कहा कि टेक्नोलॉजी को जन जन के उपयोग में लाने की जरूरत है और ये कुछ गिनी–चुनी कंपनियों के हाथों में ही सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साझा करते हुए बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बरसों तक विदेशों से मंगाया जाता था, वो अब देश में ही बन रहा है। उन्होंने बताया कि आज सेमीकंडक्टर से लेकर कई तरह की काम्प्लेक्स मॅन्युफॅक्चरिंग हमारे यहाँ हो रही है। आज ये इंडस्ट्री साढ़े ग्यारह लाख करोड़ रुपये की बन चुकी है और इससे 25 लाख लोगों को सीधे रोजगार भी मिलता है।

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचंद्र जी ने कहा कि उत्कृष्टता की भूख ने भारतीय उद्यमियों को सर्वश्रेष्ठ उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लघु उद्योगों के बेहतर संचालन और गुणवत्तापरक उत्पादों के लिए जरूरी स्किल्ड फोर्स को तैयार करने की दिशा में संगठन कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये कार्य केवल सरकार के भरोसे छोड़ना उचित नहीं होगा। उन्होंने प्रदेश के टेक्सटाइल हब पाली में संगठन के प्रयासों से किये गए कौशल विकास के कार्यों के बारे में भी जानकारी दी।

राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कौशल विकास की महत्ता को रेखांकित करते हुए लघु उद्योग भारती के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आई–स्टार्ट के माध्यम से सरकार लघु उद्योग भारती के साथ एमओयू करेगी जिससे इनक्यूबेटर को और अधिक सपोर्ट दिया जा सके। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा ने तकनीकी शिक्षा में की गई प्रगति के बारे में जानकारी साझा की। लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र शर्मा ने संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कौशल केंद्र के समन्वयक श्री महेंद्र खुराना ने केंद्र में संचालित कोर्सेस के बारे में बताया।

गौरतलब है कि आइडियाथोन–2025 में प्राप्त हुई 153 प्रविष्टियों में से जयपुर के तन्मय व्यास और चारू वैष्णव के स्टार्टअप को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इस स्टार्टअप के आइडिया से प्रभावित होकर रेल मंत्री श्री वैष्णव ने उनके प्रोटोटाइप के एक्सपेरिमेंट के लिए रेलवे के जनरल मैनेजर को मंच से ही निर्देशित किया जिसमें एआई से ट्रेन की स्पीड को बेहतर और नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा पुरस्कार मुंबई की रीतिका को बेबी फिट स्टार्टअप एवं तीसरा पुरस्कार ग्यारहवीं कक्षा की स्टूडेंट्स को मूक बधिर लोगों के लिए बनाये साइनो प्रोडक्ट को प्रदान किया गया। इस अवसर पर स्टोनमार्ट –2026 के ब्रोशर का विमोचन भी किया गया जिसमें राष्ट्रीय सचिव श्री नरेश पारीक एवं स्टोनमार्ट–2026 के संयोजक श्री नटवरलाल अजमेरा भी उपस्थित रहे।

□□□

'Pali Model' is a Unique & Effective in Social Change

Union Minister for Railways Shri Vaishnaw praises LUB for Skill Development

News Flash
Udyog Times Desk

Union Minister for Railways Shri Ashwini Vaishnav visited industrial town of Rajasthan Pali for physical observation of LUB's outstanding ground work for empowering women through Skill Development on 25th Sept. Firstly, he visited Hemawas village for a bangle-studded machine, where 10 to 15 women work simultaneously.

He then visited a clay pot manufacturing machine in the Naya Gaon RIICO Industrial Area, where he understood the entire process of making clay pots without the use of any chemicals. The railway minister described this as a major step in environmental protection and announced the use of clay pots made here in the Railways.

He also observed training programs in Sewing, Computers, Beauty Parlors, and Mehndi at the Vriddhashram Seva Samiti. After inspecting these projects, the railway minister described them as highly commendable in the field of self-reliance and employment. This "Pali Model" of self-employment was described as unique itself and effective in social change.

Shri Vaishnav wrote on X...

"India's industries have been recognized globally for centuries. Laghu Udyog Bharati has successfully modernized traditional industries. This has led to increased self-employment in rural areas. Nearly 25,000 sisters and brothers in Pali district have increased their incomes through this 'Pali Model'. This has reduced the tendency to migrate, and finding work in rural areas has reduced the need to migrate to cities. Self-employment has increased self-confidence and self-respect in society.

Thanks to Shri Prakash Chandra Gupta, the Architect of this 'Pali Model', and Shri Gyanchand Parikh, a longtime servant (sevak) of Pali."

Shri Ashwini Vaishnav in Pali Observing the Kullad Industry with LUB's National Organizing Secretary Shri Prakash Chandra ji and UDH Minister Shri Jhabar Singh Kharra.

On this occasion, LUB's National Organising Secretary Shri Prakash Chandra ji, Minister In-charge Pali District Shri Jhabarmal Kharra, Industry Minister Shri K.K. Vishnoi, MP Shri PP Chaudhary, former MLA Shri Gyanchand Parikh, District Collector Shri L.N. Mantri, SP Shri Siddharth Sidhu, Past National President Shri Ghanshyam Ojha, National EC Member Shri Shantilal Balar, State VP Shri Mahavir Chopra, State Jt. Secretary Shri Vinay Bamb, Jodhpur Prant GS Shri Suresh Bishnoi, Jt. Secretary Shri Rahul Mehta and Social Worker Shri Kamal Kishore Goyal were present.

It is noteworthy that earlier, in a program organised at the Sohan Singh Memorial Skill Development Centre of Laghu Udyog Bharati, an exclusive report on the Pali Model was presented to Shri Vaishnav.

□□□

News Update

India Stonemart-2026 Stall makes Impressive Presence at World-Class Stone Exhibition Marmomac-2025

The India Stonemart-2026 stall was inaugurated by Minister Industry & Commerce, Col. Shri Rajyavardhan Rathore on Sept. 23rd at the world-class stone exhibition Marmomac-2025 in Verona, Italy. Shri Lavanya Kumar, Consulate General Milan, and Smt. Shivangi Swarnkar-IAS, MD RIICO were also present on the occasion. Following the inauguration, the Minister was invited as Guest of Honor to the formal ceremony, where he inaugurated the Marmomac-2025 Exhibition in the presence of international exhibitors.

The Minister and the delegation then toured the exhibition and visited the stalls of Indian companies. Visiting the Indian exhibitors' booths, he learned about their activities and interacted with representatives from international stone associations and various countries.

A high-level delegation from Rajasthan participated. The delegation included LUB's National Jt. GS Shri Naresh Pareek, Stonemart-26 Convener Shri Natwarlal Ajmera, State Treasurer Shri Arun Jajodia, EC Member Shri Pukhraj Jain, CDOS VP Shri Rakesh Gupta, and CEO Shri Mukul Rastogi. Senior officials from LUB and FIGSI were also present. Around 55 companies from India actively participated in Marmomac this year. This demonstrates the growing global presence and competitiveness of the Indian stone industry.

On this occasion, Shri Col. Rajyavardhan Rathore, met with representatives from several international associations and stone importing countries and extended a special invitation to them to participate as exhibitors and visitors at the upcoming India Stonemart-2026 (February 5-8, 2026, Jaipur).

This initiative of the Laghu Udyog Bharati and Centre for Development of Stones (CDOS) will further strengthen the global image of the stone industry in India and Rajasthan and open new avenues for international collaboration and business opportunities.

Union Minister of Commerce & Industry Shri Piyush Goyal released the Brochure of India Industrial Fair (IIF-2025) at New Delhi on 9th Sept, 2025. On this occasion, National GS Shri OP Gupta, National Secretary Shri Naresh Pareek, Former National Treasurer Shri (CA) Yogesh Gautam, Rajasthan State VP Shri Natwar Lal Ajmera, Assam Unit President Shri Partha Pritam Pathak and other members. LUB's Flagship B2B Trade Exhibition is being organised by Assam Unit to be held at Guwahati on 30th Oct.-2nd Nov. 2025.

LUB's National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji visited 6 Vatikas developed by the Beawer unit of Rajasthan state on on 2nd Sept. 2025. He praised the efforts being made for tree planting, environmental protection, and

beautification of LUB's Vatika in presence of Unit Palak Shri Prakash Ambure and other members.

LUB's Ramganj Unit of Rajasthan State was reorganised in the presence of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji, AIWC Member Shri Govind Ram Mittal, State VP Shri Pawan Goyal and Shri Yashpal Bhatia on 23rd Sept. 2025.

LUB's Goa Delegation met Chief Minister Dr. Pramod Sawant regarding new GST 2.0 framework on 24th Sept, 2025. LUB Goa formally welcomed the reforms, recognizing them as a progressive measure that will directly benefit and foster growth for MSMEs across the state. On this occasion, State General Secretary Shri Mudit Agarwal, Treasurer CA Vibhor Keny, and EC Members CA Gaurav Kenkre, Shri Ajay Gramopadhye, and Shri Manoj Patil were present.

LUB's official website, http://lubindia.com, was launched in a new look by National GS Shri OP Gupta in the virtual presence of Mass Comm. Core Committee members; Shri Ateet Agarwal, Shri Abhishek Tiwari, Shri Amit Goyal and Smt. Manjula

Mishra on 2nd Sept. 2025. This new layout symbolizes the organization's progress and the strength of the MSME sector.

LUB's National GS Shri Om Prakash Gupta expressed sincere gratitude to SIDBI for participation in the unique program marking the launch of the "Developing Industry Associations (DIA)" Portal by Shri Nagaraju Maddirala, Secretary, DFS, Ministry of Finance, Govt. of India. On this occasion, LUB made a presentation on India's First Green-Transformed MSME Cluster. Further, the LUB delegation extended a warm invitation to Shri Manoj Mittal, CMD-SIDBI, to grace the 13th IIF at Guwahati, Assam, as Guest of Honour.

Industry Minister Delhi Shri Manjinder Singh Sirsa had an interaction in an insightful session on key industrial challenges, policy reforms,

and the future of MSMEs at LUB's Head office. The session was led by LUB's Delhi President Shri Diwan Chand Gupta, along with General Secretary Smt. Aarti Sehgal and Shri Virendra Nagpal.

LUB's delegation had a constructive meeting with Shri Alok Chandra, Additional Secretary MoLE and Dr. Mahendra Kumar, Joint Secretary (Industrial Safety & Health Division, MoLE). Representing LUB were Shri Madhu Sudan Dadu National President, Shri Om Prakash Gupta National General Secretary, Smt. Anju Bajaj National Secretary & Shri Ramakant Bharadwaj AIEC Member. The discussion focused on strengthening MSMEs, positively addressing certain provisions of the OSH Act (Sec. 57 & 14), and exploring MoLE's support for awareness programmes in clusters & industrial areas.

LUB's Gujarat state delegation met Industry Minister Shri Balvant Singh Rajput at Gandhinagar to present key concerns of Morbi industries on 2nd Sept. 2025. The delegation requested for reduction of GST on ceramic products and subsidy benefits for the paper mill industry be continued while revising GST slabs.

LUB's Delhi state conducted a program in presence of MCD Mayor Shri Raja Iqbal Singh and Chairperson, Standing Committee MCD Smt. Satya Sharma, National GS Shri OP Gupta, State President

Shri Diwan Chand Gupta, GS Smt. Aarti Sehgal, and Treasurer Shri Kumar Pal on 2nd Sept. LUB's office bearers formerly thanked to MCD for remarkable initiative of removing factory licensing which will significantly ease business operations for MSMEs.

An MoU was signed between Laghu Udyog Bharati & University of Rajasthan for coordination in education, incubation, and skill development at Jaipur on 3rd September. Vice-Chancellor Prof. Alpana Kateja, Registrar Shri Rajkumar Kaswa, LUB's State GS Shri Sudhir Garg, VP Smt. Anju Singh, VP Shri Mahendra Khurana, Jaipur Anchal President Shri Mahendra Mishra & GS Ms. Sunita Sharma were present.

LUB's Bhopal Women Wing organized Swayamsiddha Navratri Exhibition on 25th to 29th Sept. 2025. The exhibition successfully achieved its objective of promoting tradition, culture, and indigenous products. The occasion was graced by the presence of former national Jt. GS Shri Sudhir Date, former Treasurer Shri Naveen Borkar, and Patron Smt. Purnima Date.

LUB's Bikaner Unit & Commercial Tax Department jointly organized Samwad in the presence of Additional Commissioner Commercial Tax Shri KL Jasol and LUB's Jodhpur Prant President Shri Balkishan Parihar under Bachat Utsav-2025 on 28th Sept. The objective of the program was to provide information about the reduction in tax rates related to GST 2.0 and to resolve the misconceptions among the traders.

Under the aegis of Ministry of Labour and Employment & LUB's Alwar Unit, the 5th camp of "Suvidha Samagam" was organized by ESIC on 29th Sept. President Shri Shashank Jhalani, Secretary Shri Pankaj Tiwari, and other office bearers were present in the program.

LUB's Saharanpur Unit (UP) conducted Udyami Samwad and Industrial Visit in the presence of Commissioner Shri Atal K. Roy on 29th Sept. 2025.

LUB's Tamil Nadu State Unit opened its New Office on 29th Sept. 2025.

LUB hosted an Internship Orientation at Head Office for students of Zakir Husain College, Delhi University on 27th Sept. The session was graced by President Delhi Shri Diwan Chand Gupta, General Secretary Smt. Aarti Sehgal and Treasurer Shri Kumar Pal, National Coordinator - Industry Academia Smt. Jayanti Goela, Nodal Officer - Research & Industry Collaborations Dr. Arshpreet Kaur and Faculty, Zakir Husain Delhi College, DU Shri Jagdish Bishnoi.

LUB's Meerut Unit organised Udyami Samwad in the presence of MoS Excise & Prohibition, Govt. of UP Shri Nitin Agarwal on 27th Sept. 2025.

An awareness program was organized jointly by LUB's Aligarh Unit and SIDBI in

the presence of SIDBI Chairman & MD Shri Manoj Mittal, GM Shri Rajiv, LUB's National Secretary Shri Deepak Agarwal, State Jt. GS Shri Gaurav Mittal on 26th Sept. On this occasion, a new branch of SIDBI was inaugurated also.

LUB's National President Shri Madhusudan Dadu addressed a gathering in presence of Union Minister for MSME Shri Jitan Ram Manjhi and Cabinet Minister Industry, UP Shri Rakesh Sachan in the flagship event of UP Govt. 'UPITS-2025' (UP International Trade Show) at India Expo Centre & Mart, Greater Noida held on 25--29 Sept. 2025. MSME Minister appreciated all solutions suggested by Shri Dadu regarding core issues of MSMEs.

An Awareness Workshop on RAMP (Raising & Accelerating MSME Performance) was jointly conducted by LUB's Sikar unit & Ministry of MSME, Govt. of India on 26th Sept. The workshop detailed the 2024 MSME Policy.

On this occasion, RM-RIICO Shri Gurmeet Singh, State GS Shri Sudhir Garg, State EC Member Shri Sanjay Mor and Shri Shravan Kaler.

LUB's Kerala State Working Committee meeting was conducted at Chalakudy on 26th Sept. 2025.

Shri Dinesh Gupta was appointed as LUB's J&K and Ladhak State President on 26th Sept. 2025. Earlier; Shri Gupta has worked as Vice President of State EC.

LUB's Jharkhand State Unit & Aadityapur Small Industries Association (ASIA) jointly organised ESIC Seminar. ESIC Regional Director Shri Rajiv Ranjan, Assistant Director Shri Abhishek Kumar, Dr. P.K. Singh, State In-charge Shri Inder Agarwal, Saraikela-Kharsawan District President Shri Vinod Sharma were present. It was successfully conducted by Shri Pradeep Gutgutaya, General Secretary of ASIA.

LUB's Roorkee Unit (UP) and Federation of Indian Export Organisation jointly conducted

an awareness program on Exports thru E-Commerce on 23rd Sept. 2025.

LUB's National GS Shri Om Prakash Gupta and National Jt. GS Shri Ashish Deorah extended a warm invitation to CMD-NSIC, Dr. Subhransu Sekhar Acharya to join the 13th IIF Guwahati for focusing on marketing support & capacity building schemes on 24th Sept. 2025.

LUB's Satna unit (MP) submitted a memorandum to the Collector's office on 24th Sept., formally requesting to allocate land for a skill centre and permanent office for the unit.

At the annual meeting of LUB's Bagru unit, DIC (GM) Shri Subhash Sharma and District Officer Shri Anand Sharma provided detailed information about the new schemes of Rajasthan Govt. National Secretary Smt. Anju Singh spoke about the Stone Mart. State EC member Shri Kavindra Julka, Unit President Shri Rajendra Maheshwari, and Secretary Shri Surendra Kabra were present.

LUB's North Bengal Team headed by President CA Aditya Mitruka met Union MoS for Agriculture and Family Welfare Shri Bhagirath Choudhary and discussed several key issues related to the inclusion of tea in the agriculture sector and GST reforms at Siliguri during his visit to Sikkim.

LUB's Tamil Nadu State President Dr. Verchezian and the Chennai team signed an MoU with the Tamil Nadu State Council for Science & Technology for Technology Transfer and Patent Filing Services for all MSMEs across the state on 23rd Sept. Additionally, they have several patented products that MSMEs can adopt and start manufacturing.

LUB's Gujarat State Unit and DMMA Team jointly met FDCA Commissioner, Dy. Health

Secretary and Dy. Drug Controller regarding core issues of Pharma Sector on 23rd Sept. 2025.

LUB's Mumbai unit tied up with Patkar-Varde College, Goregaon and organized a Campus Recruitment Drive to hire Interns, on 9th Sept. 2025. The aim was to bring Industry and Institution together and bridge the gap between classroom learning and real-world industry exposure. This initiative gives students hands-on experience and exposure while studying, and helps industry find fresh talent.

LUB's delegation of J&K and Ladakh, led by State President Shri Parveen Pargal and accompanied by State Secretary Finance Shri Ishant Gupta and Shri Rajinder Sadotra, attended the MSME Conclave organised by Amar Ujala. The delegation had a meaningful interaction with Cabinet Minister for Industries, Govt. of J&K, Shri Surinder Choudhary, and highlighted key industry issues including NCSS and Purchase & Price Preference.

LUB's Purvottar unit held a detailed interaction with Smt. Neetika Bansal, Director-KPMG's Logistics & Mobility Team, and her colleagues on 21st Sept. KPMG as knowledge partner of SIDBI is conducting a study on Assam's logistics environment and MSME challenges. LUB shared key inputs on high transportation costs, need for multimodal connectivity, modern warehousing, digital solutions, and policy support for logistics MSMEs. LUB members Shri Vikash Agarwal, Shri Alok Sonthalia, Shri Beejeet Prakash, Shri Shiv Soni, and Shri Rohit Agarwal were present.

LUB's Goa Unit and IGNITE jointly organised the Industry-ITI Meet 2025. The open forum provided an opportunity for industry leaders, ITI representatives, and industry representatives to exchange ideas on uplifting ITIs, enhancing training quality, and creating better career pathways for youth. LUB was represented by President Smt. Pallavi Salgaocar, VP Shri Jayesh Raikar and other members.

LUB's Gems & Jewellery Unit conducted an Awareness Program for entrepreneurs at Jaipur on 20th Sept. 2025.

The Udyami Sammelan and All India Adhiveshan-2025 have been successfully organized as a Net Neutral Event by adopting mindful practices and offsetting unavoidable emissions through certified carbon credits. It was a proud moment when Haryana CM Shri Nayab Singh Saini presented the

Carbon Neutrality Certificate to National President Shri Ghanshyam Ojha and General Secretary Shri O.P. Gupta on 15th Sept. The LUB express its heartfelt thanks to Shri Kaushal Goel (KBS) for leading the certification process, and LUB Haryana Team for their dedicated support in data collection.

LUB's Women Wing Bhilwara (Rajasthan) conducted Blood Donation Camp on Vishwakarma Jayanti on 19th Sept. 2025.

The LUB was honoured to be part of a high-level delegation meeting of the Parliamentary Standing Committee on Science & Technology, Environment, Forests and Climate Change, held at CSIR-CSIO, Chandigarh on Sept 19, 2025. Smt. Aarti Sehgal, National Coordinator CSIR & General Secretary, Delhi and Dr. Arshpreet Kaur, Nodal Officer - Research & Industry Collaboration were present. The event featured an impressive exhibition of cutting-edge technologies developed by CSIO scientists, many of which are ready for industrial commercialization and highly relevant to the MSME sector.

LUB's Delhi State Unit and ESIC Hospital jointly organized Free Health Check-up Camp exclusively for women employees in the Mayapuri Industrial Area on 19th Sept. Specialist doctors provided on-site medical examinations, bringing essential healthcare services directly to the workplace.

The Industries & Commerce Department (Group-2), Govt. of Rajasthan has nominated 4 members of Laghu Udyog Bharati for Joint Working Group, which includes National Jt. GS Shri Naresh Pareek, former State President Shri Shantilal Balar, State VP Shri Mahendra Khurana and prominent entrepreneur Shri Mukesh Agarwal, Kishangarh. This group will discuss the challenges of industry and present meaningful suggestions to the government. The organisation expressed its gratitude to the Industry & Commerce Minister Col. Rajyavardhan Singh.

LUB & Swaniti Initiative signed an MoU to collaborate on the Energy Transition Index (ETI) project on 18th Sept. The event was graced by National

President Shri Madhusudan Dadu, National GS Shri Om Prakash Gupta, National Coordinator- Net Zero & Industry Academia Smt. Jayanti Goela, along with other office bearers from Swaniti Initiative, Trustee Smt. Uma Bhattacharya, Vertical Lead - Policy Engagements Shri Abhishek Kumar, and CEO Smt. Rwitwika Bhattacharya on virtual mode.

LUB's North Bengal organized an Interactive Session on the Next Generation GST Reforms at Siliguri, Darjeeling District on 16th Sept. 2025.

LUB's Erode (TN) GAIN Cluster product was launched by UP CM Shri Yogi Adityanath. This product-108 Petals Lotus Tea was developed under LUB-TN CSIR-NBRI Technology Transfer by Smt. Kiruthika and launched in the UP Startup-CSIR program.

LUB's Kashi Prant (UP) and Mauritius had a fruitful discussion to Boost Economy of Uttar Pradesh.

MSME Ministry sponsored Workshop for Awareness on MSME Competitive LEAN Scheme was organised by Laghu Udyog Bharati, Lucknow Management Association & National Productivity Council, Kanpur on 17th Sept., 2025.

LUB's Delhi State Delegation headed by President Shri Diwan Chand Gupta met Additional Commissionaer Finance MCD Shri Veer Singh Yadav regarding long standing issues of Factory Licence and House Tax faced by MSMEs on 12th Sept. 2025.

LUB's Sukher Unit (Udaipur) and Marble Processors Samiti organised a Plantation Drive on 9th Sept. 2025.

LUB & Vidyalankar Polytechnic (VP) Mumbai signed a MoU to strengthen MSME growth through industry-academia collaboration on 8th Sept., 2025, Key initiatives under the collaboration include: Launch of AI and digitization pilots to help small businesses automate processes, modernize operations, and become future-ready Facilitating student internships and capstone projects with MSMEs to provide exposure to grassroots industry challenges and create practical solutions. The MoU was formalized in the presence of National GS Shri Om Prakash Gupta, National Coordinator Industry-Academia Smt. Jayanti Goela, President LUB Mumbai Unit Shri Jayesh Dedhia along with members. From Vidyalankar Polytechnic, Prof. Dr. Ashish Ukidve (Principal), Dr. Vaishali Malkar (Vice Principal), Prof. Vijay Patil (HoD), Prof. Anjum Mujawwar, Prof. Yogita K., Dr. Sandhya, and other faculty members participated.

LUB's Gram Shilpi Project Convener Shri Sameer Mundra reviewed the Work on North-East Visit with Shri Manoj Lundia, Assam State Secretary Shri Pramod Kumar Mour at Guwahati on 5th Sept. 2025.

LUB's Gwalior Unit (MP) Delegation met Commissioner Nagar Nigam Shri Sangh Priya IAS for Industrial Issues on 5th Sept. 2025.

The ONDC (Open Network for Digital Commerce) Awareness Program was organized by NSIC, BO-Kolkata, Associate Partner LUB South Bengal, in collaboration with the Ministry of MSME's Trade Enablement and Marketing (TEAM) initiative at Kolkata on 3rd Sept. 2025.

The program aims to equip artisans and MSME with practical knowledge and tools to integrate into the open digital commerce ecosystem.

LUB's Ghaziabad (UP) Delegation met Additional Commissioner Shri Manvendra Pratap Singh regarding GST Issues faced by MSMEs on 2nd Sept. 2025.

□□□

बरषत हरषत लोग सब, करषत लखै न कोइ।
तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु सो होइ ।।

इस साल की दीपावली
हर घर खुशहाली

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवाएं एवं वाहन समेत

अनेक वस्तुएं हुई सस्ती

दैनिक उपयोग की वस्तुएं

वस्तु	पहले	अब
हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट	18 %	5 %
मक्खन, घी, चीज़, नमकीन, भुजिया	12 %	5 %
बर्तन	12 %	5%
बच्चों की बोतलें व डायपर	12 %	5%
सिलाई मशीन	12 %	5%

शिक्षा

वस्तु	पहले	अब
मैप्स, चार्ट, ग्लोब	12 %	Nil
पेंसिल, शार्पनर	12 %	Nil
कॉपी व नोटबुक	12 %	Nil
रबर (Eraser)	5%	Nil
क्रेयॉन्स	12 %	Nil

हेल्थकेयर

वस्तु	पहले	अब
हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस	18 %	Nil
36 जीवन रक्षक दवा	12 %	Nil
दवाइयां एवं चश्मा	12 %	5%
थर्मामीटर	18 %	5%
मेडिकल ऑक्सीजन	12 %	5%
डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर व स्ट्रिप्स	12 %	5%

किसान एवं कृषि क्षेत्र

वस्तु	पहले	अब
ट्रैक्टर टायर	18 %	5 %
ट्रैक्टर	12 %	5 %
बायो-पेस्टिसाइड्स	12 %	5%
ड्रिप इरिगेशन, खेती मशीनें	12 %	5%

वस्त्र, कपड़ा एवं जूते

वस्तु	पहले	अब
पॉलिएस्टर, नायलॉन	18% / 12%	5 %
रेयान फाइबर और धागा	18% / 12%	5 %
कालीन, मैट्स, टॉवेल, लेस, कढ़ाई	12 %	5 %
₹2500 तक के जूते	12 %	5 %

इलेक्ट्रॉनिक्स

वस्तु	पहले	अब
एसी	28%	18%
टीवी (32 इंच से ऊपर)	28%	18%
मॉनिटर व प्रोजेक्टर	28%	18%
डिश वाशिंग मशीन	28%	18%

पर्यटन, ऊर्जा एवं उद्योग

वस्तु	पहले	अब
होटल ठहराव (₹7500 प्रतिदिन तक)	12 %	5 %
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा उपकरण	12 %	5 %
सीमेंट	28 %	18%

हेण्डीक्राफ्ट एवं कला

वस्तु	पहले	अब
लकड़ी, पत्थर, धातु की मूर्तियां	12 %	5 %
हस्तशिल्प वस्तुएं	12 %	5 %
खिलौने, पेंटिंग्स	12 %	5 %

ऑटोमोबाइल

वस्तु	पहले	अब
हाइब्रिड कार डीज़ल हाइब्रिड कार	28%	18%
3 व्हीलर मोटरसाइकिल (350cc तक)	28%	18%
मालवाहक वाहन	28%	18%

22 - 29 सितम्बर, 2025

जीएसटी बचत उत्सव

घटी जीएसटी मिला उपहार - धन्यवाद मोदी सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

UDYOG TIMES | OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI | 30 September - 2025 | Registration No. RAJBIL/2016/69093
Postal Reg. No. : Jaipur City/433/2020-22

Follow us

- lubindia
- @lubBharat
- laghu-udyog-bharati
- lubindia
- lub.india

LUB's Monthly Magazine Published by OP Mittal Printed at Raj Blocks, 22 Godown Ind. Area Kartapura, JAIPUR-302019